दैनिक
कारखाने का सफर
मुकाबले के चक्कर में आदमी का जीवन एक कारखाने के समान हो गया है, आदमी का सबसे विश्वसनीय अखबार

अब उज्बेकिस्तान में भी चलेगा भारतीय... पेज 5

आखिर सुदामा के श्राप से क्यों धरा... पेज 7

वर्ष 7, अंक 73 | भोपाल, सोमवार 31 अगस्त, 2026 | भाद्रपद कृष्ण पक्ष, तृतीया, 2083 | मूल्य 2 रुपए

राधा कृष्ण मंदिर बरखेड़ा में रासलीला एवं ब्रज की होली के साथ दूसरे दिन 2.51 लाख ईनाम की भोजपाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता

जन्माष्टमी के मौके पर भोजपाल महोत्सव समिति के भेल क्षेत्र में राजधानी के दो सबसे बड़े आयोजन

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

जन्माष्टमी के मौके पर भोजपाल महोत्सव समिति के भेल क्षेत्र में राजधानी के दो सबसे बड़े आयोजन हो रहे हैं। पहला 4 सितंबर को राधा कृष्ण मंदिर बरखेड़ा में रासलीला एवं ब्रज की होली के साथ दूसरे दिन 5 सितंबर को 2.51 लाख ईनाम की भोजपाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता हेलीपैड अवधपुरी तिराहे पर होगी। यह मटकी फोड़ प्रतियोगिता प्रदेश की सबसे बड़ी मटकी फोड़ प्रतियोगिता में गिनी जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर 4 सितंबर को राधा कृष्ण मंदिर बरखेड़ा में रासलीला एवं ब्रज की होली का आयोजन किया गया है। इसमें राजधानी सहित आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल होंगे। हर साल की तरह यह कार्यक्रम जन्माष्टमी के दिन शाम को 7:00 बजे शुरू होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष व भोजपाल महोत्सव मेला समिति के अध्यक्ष के भेल यादव समाज के पदाधिकारी सुनील यादव ने बताया कि हर साल राधा कृष्ण मंदिर बरखेड़ा में जन्माष्टमी के मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा होती है। इस मौके पर भजन संध्या व बृज की होली के साथ महाप्रसादी वितरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी वासियों से अपील की गई है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान राधा कृष्ण का आशीर्वाद लें। जन्माष्टमी के दूसरे दिन अवधपुरी हेलीपैड पर प्रदेश की सबसे बड़ी 2.51 लख रुपए की मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है इसमें भी पूरे प्रदेश से काफी संख्या में लोग भाग लेने आते हैं।

2.51 लाख की इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता 5 सितंबर को : इंडियन आइडल-11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी देंगे प्रस्तुति, 15 से अधिक गोविंदा टोलियां लेंगी हिस्सा- भोजपाल महोत्सव मेला समिति की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन 5 सितंबर को प्रदेश की बड़ी इनामी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अवधपुरी चौराहा स्थित विवेकानंद स्कूल के सामने हेलीपैड मैदान पर शाम 7.30 बजे से होने वाले इस आयोजन में 2.51 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर होगी। प्रतियोगिता में प्रदेश और आसपास के जिलों से 15 से अधिक गोविंदा टोलियां शामिल होंगी। आयोजन का मुख्य आकर्षण इंडियन आइडल-11 के विजेता सनी हिंदुस्तानी की प्रस्तुति होगी। वे अपने मधुर गीतों के जरिए गोविंदा टोलियों और दर्शकों का उत्साह बढ़ाएंगे।

भक्ति और मनोरंजन का होगा संगम

भोजपाल महोत्सव मेला समिति के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि मटकी फोड़ प्रतियोगिता को भव्य स्वरूप देने की तैयारियां चल रही हैं। संयोजक विकास वीरानी ने बताया कि आयोजन स्थल पर आकर्षक सजावट, संगीत और भक्ति गीतों के साथ शहरवासियों को भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। हजारों श्रद्धालुओं के आयोजन में पहुंचने की उम्मीद है। महामंत्री हरीश कुमार राम ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान रंग-बिरंगी आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी। आयोजन परिसर को आकर्षक विद्युत साज-सज्जा से सजाया जाएगा।

30 मिनट की बारिश बनी आफत! अचानक आई भीषण बाढ़ से 15 सैलानी लापता

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

अमेरिका के विश्वप्रसिद्ध ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क में अचानक आई भीषण बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने वहां मौजूद सैलानियों और कैंपर्स के लिए भारी तबाही मचा दी है। मूसलाधार बारिश के बाद आए पानी के तेज़ और कीचड़ भरे बहाव ने इलाके के बुनियादी ढांचे को तहस-नहस कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, लगभग 15 लोगों के लापता होने की आशंका है, जबकि बचाव टीमों ने अब तक 62 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे काइबाब पठार (Kaibab Plateau) पर हुई भीषण बारिश के बाद हालात अचानक बिगड़ने लगे। बारिश का पानी खड़ी ढलानों से होता हुआ बेहद तेज़ रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ा, जिससे कोलोराडो नदी में मिलने वाली ब्राइट एंजेल क्रीक का जलस्तर कुछ ही मिनटों में खतरनाक स्तर पर पहुँच गया। अधिकारी उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रभावित इलाके में हाइकिंग या कैंपिंग कर रहे होंगे। किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है।

नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक, शनिवार को काइबाब पठार पर बारिश के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे बाढ़ आनी शुरू हुई। कोलोराडो नदी में मिलने वाली ब्राइट एंजेल क्रीक का जलस्तर तेज़ी से बढ़ा क्योंकि बारिश का भारी पानी खड़ी ढलान वाली घाटी से तेज़ी से नीचे आया। पानी के तेज़ बहाव ने क्रीक पर बने पैदल पुलों को बहा दिया और इलाके की बनावट को काफी बदल दिया; क्रीक का तल चौड़ा हो गया और ऐसा लगा मानो नदी में पानी की तेज़ लहरों वाला एक नया हिस्सा बन गया हो।

हाइकिंग करने वालों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कीचड़ भरे पानी को रास्तों और पैदल पुलों के नीचे से तेज़ी से बहते हुए देखा जा सकता है, जिसमें लकड़ी के लट्ठे और अन्य मलबा भी बह रहा है। एरिका वियोला, जो बारिश शुरू होने के समय ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड में थीं, ने बताया कि उन्होंने और करीब 50 अन्य हाइकर्स ने इलाके में मलबा बहने से पहले क्रीक का जलस्तर बढ़ते देखा। उन्होंने बताया कि बाद में उनके ग्रुप को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे उनकी यात्रा दो दिन पहले ही खत्म हो गई।

रविवार सुबह तक 62 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, और कुछ और लोगों को भी निकाले जाने की योजना थी। फैंटम रैंच से 60 से ज़्यादा लोगों को निकाला गया; यह रैफ्टिंग करने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह है जहाँ एक ऐतिहासिक कैंटीन और डॉरमेट्री भी है। नेशनल पार्क सर्विस ने कहा कि वह एरिजोना के अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित निकालने और लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रही है।

ब्राइट एंजेल कैंपग्राउंड, फैंटम रैंच और नॉर्थ काइबाब ट्रेल के कुछ हिस्सों समेत लोकप्रिय इलाके रविवार को बंद रहे क्योंकि अधिकारी नुकसान का जायजा ले रहे थे। कोलोराडो नदी पर राफ्टिंग ट्रिप भी फिलहाल रोक दी गई हैं। फ्लैगस्टाफ में नेशनल वेदर सर्विस के मौसम विज्ञानी जस्टिन जोंड्रो ने बताया कि पथरीले इलाके में लगभग 30 मिनट के अंदर आधा से एक इंच बारिश हुई। जोंड्रो ने कहा, "ज़्यादातर पानी तुरंत बह गया।" उन्होंने बताया कि बाढ़ ग्रैंड कैन्यन के उत्तरी हिस्से में आई, जहाँ ब्राइट एंजेल क्रीक नॉर्थ रिम से कोलोराडो नदी की ओर लगभग 6,000 फीट नीचे उतरती है। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कोलोराडो रिवर स्टडीज़ के डायरेक्टर जैक श्मिट ने इस घटना को इस बात की याद दिलाने वाला बताया कि ग्रैंड कैन्यन का लैंडस्केप कितना गतिशील और सक्रिय हो सकता है।

बाढ़ से ग्रैंड कैन्यन नेशनल पार्क को पानी सप्लाई करने वाली एक मुख्य पाइपलाइन को भी नुकसान पहुँचा। नुकसान के बाद, अधिकारियों ने पार्क के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले इलाके में पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगाने की घोषणा की। नेशनल पार्क सर्विस ने लकड़ी और चारकोल से आग जलाने पर भी रोक लगा दी। रात में रुकने की कुछ सुविधाएं

उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी, कहा- यह 1.4 अरब भारतीयों का सम्मान है

दैनिक कारखाने का सफर। एजेंसी नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान के प्रतिष्ठित सम्मान 'ओली दराजाली दोस्तलिक' से नवाजा गया। उन्होंने यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच "स्थायी" संबंधों को समर्पित किया। मोदी व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा और संपर्क समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत करने के लिए उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री को यह सम्मान उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने प्रदान किया। मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, '' 'ओली दराजाली दोस्तलिक' सम्मान प्राप्त कर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच स्थायी संबंधों को समर्पित करता हूं।'' मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ''उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है।'' उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस सम्मान के नाम में प्रयुक्त शब्द 'दोस्तलिक' से भली-भांति परिचित हैं। उन्होंने कहा, ''भारत में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा, जहां 'दोस्तलिक' शब्द दिन में सौ बार न बोला जाता हो। आज आपने वास्तव में इस शब्द के सार को सामने ला दिया है। 'दोस्तलिक' का अर्थ मित्रता है। यह शब्द अपने आप में भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों के केंद्र में मौजूद भावना को खूबसूरती से व्यक्त करता है।'' मोदी ने कहा कि यह सम्मान प्राप्त करना उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा, ''सभी भारतीयों की ओर से, मैं उज्बेकिस्तान

की जनता, सरकार और अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सर्वोच्च सम्मान को बहुत विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं और इसे हमारे दोनों देशों के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा हमारी साझा विरासत को समर्पित करता हूं।'' इससे पहले, मोदी ने मिर्जियोयेव के साथ वार्ता की, जिसके बाद भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से एक सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताशकंद से किर्गिस्तान की यात्रा करेंगे। -पेज 5 भी पढ़ें

स्वच्छता से सुंदरता और जागरूकता से सुरक्षा-क्रिस्टल कैंपस ने दिया दोहरा संदेश

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

"स्वच्छ कैंपस—स्वस्थ जीवन, जागरूक नागरिक—सुरक्षित परिवार" के संदेश के साथ क्रिस्टल कैंपस वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में क्रिस्टल कैंपस, अवधपुरी, भेल, भोपाल में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9:30 बजे टंकी के नीचे, पार्क नंबर-2 से स्वच्छता अभियान के साथ हुई। सोसायटी के पदाधिकारियों एवं कैंपसवासियों ने स्वयं आगे बढ़कर श्रमदान किया और परिसर की साफ-सफाई की। इस दौरान स्वच्छता को केवल अभियान नहीं, बल्कि दैनिक जीवन की जिम्मेदारी बनाने का संकल्प लिया गया।

इसके बाद दोपहर 12 बजे साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशेषज्ञों ने लोगों को ऑनलाइन ठगी, साइबर फ्रॉड, ओटीपी, यूपीआई एवं डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए। उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे मजबूत हथियार जागरूकता और सतर्कता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्रिस्टल कैंपस वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष मनोज कुमार दीक्षित ने कहा कि स्वच्छता और सुरक्षा दोनों ही हमारे सामूहिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। एक ओर स्वच्छ वातावरण हमारे स्वास्थ्य और जीवनशैली को

बेहतर बनाता है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा के प्रति सजग रहना प्रत्येक परिवार के लिए आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि "जब हम अपने घर के साथ अपने कैंपस की जिम्मेदारी निभाएंगे और डिजिटल दुनिया में भी सतर्क रहेंगे, तभी एक बेहतर, सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।"

कार्यक्रम के अंत में क्रिस्टल कैंपस वेलफेयर सोसायटी के महासचिव बल बहादुर सिंह ने दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सदस्यों एवं कैंपसवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता से ही ऐसे सामाजिक एवं जागरूकता कार्यक्रम सफल होते हैं। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग और सहभागिता बनाए रखने की अपील की।

कार्यक्रम में सोसायटी के पदाधिकारियों एवं कैंपसवासियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को स्वच्छता अपनाने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संदेश दिया गया।

दैनिक कारखाने का सफर अखबार का संपादकीय कार्यालय
गोबिंद टॉवर, क्वालिटी रेस्टोरेंट के पास, एसबी स्टूडियों के ऊपर पिपलानी पेट्रोल पंप के पास, सोनागिरी चौराहा रायसेन रोड भेल भोपाल। मोबाइल नंबर: 9826035849, 9425006706

युवा उधमी, युवा आइकन उच्च शिक्षा बड़े पद पैकेज के बाद भी कर रहे सामाजिक सरोकार के कार्य, युवा समागम में मिला युवाओं को मोटिवेशन

आत्मिक शांति के लिए अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने की आवश्यकता हे -आचार्य समय सागर

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

आचार्य श्री समय सागर महाराज के सानिध्य में राष्ट्रीय युवा समागम में वर्तमान की उलझनों में युवाओं को जीवन में सही दिशा बोध के देश विदेश से आए वक्ताओं ने मोटिवेशन दिया, दयोदय महासंघ के तत्वाधान में, अनुशासन के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय युवा समागम की शुरुआत आचार्य विद्यासागर महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ शुरुआत हुई, राष्ट्रीय युवा समागम में ये बात उभर कर आई युवा आइकन उच्चशिक्षित बड़े पैकेज के बाद भी सहयोग की भावना से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं,मुख्य अतिथि विधान सभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे, उन्होंने आचार्य श्री को श्रीफल भेट कर पाद प्रक्षालन किया, उन्होंने कहा आचार्य विद्या सागर महाराज का तप त्याग संयम का मार्ग आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हे, उन्होंने कहा ये मत सोचना बुढ़ापे में भजन करना हे जो करना हे आज ही करो कोई भी क्षेत्र हो आपमें ही धर्म का समाज का देश का भविष्य सुरक्षित हे टेक्नोलॉजी सुविधा के लिए हे इसका उपयोग कंट्रोल के साथ करो, 2025 में पायलट बनी अशोक नगर की 26 वर्षीय पलक जैन ने कहा हम सभी को मिलकर आचार्य श्री के सपने इंडिया से भारत की ओर बढ़कर देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना हे, भोपाल की 30 वर्षीय सिविल जज ने अंकिता जैन ने कहा न्याय सबका अधिकार हे, हर वर्ग को न्याय मिले ऐसी व्यवस्था होना चाहिए वर्षायोग समिति प्रवक्ता सुनील जैनाविन अंशुल जैन ने बताया संचालन कर रहे दयोदय महासंघ के महामंत्री राकेश जैन ने कहा 15 राज्यों में 172 गो शाला संचालित हो रही हे युवा दयोदय महा संघ का आव्हान किया, इसमें युवाओं ने हाथ उठाकर संकल्प लिया जुड़ने का, अनुशासन संस्था के डॉक्टर सुधीर जैन ने कहा अनुशासन संस्था के तत्वाधान में वर्तमान में चार महिला डीएसपी बनी उन्होंने भोपाल में नहीं बिल्डिंग का आह्वान किया तो तुरंत सहयोग के लिए हाथ खड़े हुए,, चातुर्मास समिति के अध्यक्ष पंकज जैन ने अपने उद्बोधन में युवाओं को जोड़ने से आयोजन की आवश्यकता बताते हुए कहा जैन समाज हमेशा ऐसे कार्यों के लिए क्रियाशील रहेगी , अनेक राज्यों से आए युवाओं ने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी सभी की बातों में एक सर नजर आया शिक्षा और अपने जॉब के साथ भारतीय संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए कार्य करते रहेंगे और आचार्य श्री का जो मार्गदर्शन है जो उनका सपना है उसे पूरा करने के लिए सब कुछ लगा देंगे अनेक युवा हथकरघा और गौ सेवा से जुड़कर सामाजिक समरसता के कार्य भी कररहे हैं , ऑनलाइन जुड़े अहमदाबाद के युवा आइकन24 वर्षीय राज मेहता जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी बनाई और मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने व्हीकल का निर्यात विदेश में करने लगे राज मेहता ने कहा उन्होंने हमेशा अपनी संस्कृति जैन सिद्धांत का पालन किया स्वामी विवेकानंद के शब्द साधन और संसाधन हमेशा स्वदेशी होना चाहिए उसे पर कार्य करते हैं और परस्परहो जीवनाम को धारण कर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी चुना ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और सत्य हमें क्रिटिकल बनता है अपरिग्रह ग्राउंड साइंस रखता है, अपने देश की संस्कृति और संस्कारों को विदेशों तक प्रचार करने के लिए मलेशिया में 20 देश के प्रतिनिधिमंडल में वह हथकरगा धोती दुपट्टा पहन कर गए देश की संस्कृति को बढ़ावा देने वह महीने में एक बार हुई दुपट्टा बड़ी बिजनेस मीटिंग में पहनते हैं अपनी बात रखने ऑनलाइन जुड़ी अमरीका से डॉ सुरभि पंड्या ने भी अपने अनुभव बताए, राहुल जैन पुणे मल्टी नेशनल कंपनी में लगभग 1 करोड़ के पैकेज केबाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर जैन युवा संघ के द्वारा प्राचीन मंदिरों का जिम्नोद्धार प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के लिए औषधालय आदि का निर्माण और शिक्षा के लिए सहयोग की भावना से कार्य कर रहे हैं उनके साथ अनेक उच्च शिक्षित युवा जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा हमको सबका सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए यह लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा इन कार्यों में लगाते हैं जैन युवा संघ से जुड़े चार मुनिराज संघ में साधना कर रहे हैं , जैन संघ के अनेक युवा ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साधना कर रहे हे,आचार्य श्री श्री से प्रश्न करते युवा शुभम ने पूछा टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है,, इसका सदुपयोग से ज्यादा दुरूपयोग ज्यादा हो रहा है,, हम टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करें कि इसके दुष्परिणाम नहीं आए,,, दमोह से आए निखिल ने पूछा आचार्य श्री मंदिर और जल तो बहुत बढ़ रहे हैं बड़े-बड़े विशाल बनते जा रहे हैं पर संस्कारों के अभाव में आने वाले समय में धर्मात्मा बचेंगे कि नहीं इन मंदिर और जिनालयों की रक्षा कैसे होगी , 2025 में पायलट बनी पलक जैन ने कहा सभी का सहयोग करते हुए मिलकर इंडिया से भारत की ओर चले ओर देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाए, कम उम्र में सिविल जज बनी अंकिता जैन ने कहा सफलता के लिए मन को संकल्पित कर मंजिल की ओर लगना पड़ता हे, दयोदय महासंघ के महामंत्री राकेश जैन अनुशासनदय के डॉ सुधीर जैन ने संचालन किया, आचार्य समय सागर महाराज ने कहा भावो की शुद्धि से आगे बढ़ोगे , धर्म को परिभाषित करने से अच्छा प्रयोगिक करो जिसके अंदर दया करुणा है वही धर्मात्मा हे, अहिंसा विश्व धर्म हे, आदर्श जीवन से ही धर्म के प्रति आकर्षित होगे, आज मर्यादाओं के उल्लंघन से नैतिकता का पतन हो रहा हे , प्रदर्शन से दूर रहो, दर्शन की ओर ध्यान दो, भावो की पवित्रता से जीवन सार्थक हे शारीरिक सुख तो क्षणिक होता है आत्मिक सुख के साथ अर्थ से परमार्थ की और बढ़ो,, समाज में अनुशासन बहुत जरूरी है या यू कहे कि अनुशासन हमारे धर्म समाज और देश के विकास के लिए रीड की हड्डी है हमेशा परिणाम एक से नहीं होते परिणाम को एडजस्ट करके चलना पड़ता है क्योंकि वातावरण हमेशा अलग-अलग मिलता है जो प्रतिकूल है अनुकूल हो सकता है अनुपात का ध्यान रखोगे तो और जो अनुकूल है वह प्रतिकूल हो सकता है अनुपात के अभाव में दयोदय के महामंत्री राकेश जैन अनुशासन के डॉक्टर सुधीर जैन ने बताया मुख्य अतिथि और समाज की प्रतिभाओं का सम्मान वर्षा योग समिति के पदाधिकारियों ने किया।

सीबीआई से एमईए होते हुए यूएई कोर्ट पहुंचेगा केस

विदेश में छिपे आरोपी को लाने मप्र एसटीएफ की पहली प्रत्यर्पण कवायद

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

निवेश के नाम पर देशभर में 3200 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी लविश उर्फ लविश चौधरी को दुबई से भारत लाने के लिए मप्र एसटीएफ ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तकरीबन पूरी की है। मप्र की किसी जांच एजेंसी द्वारा विदेश में छिपे आरोपी को प्रत्यर्पित कराने की यह पहली ऐसी कवायद है। लविश के खिलाफ ब्लू के बाद रेड नोटिस जारी कराया जा चुका है। ब्लू नोटिस से एसटीएफ को उसके दुबई में होने और लोकेशन की पुष्टि हुई थी। प्रत्यर्पण के लिए केस से जुड़े करीब 200 दस्तावेज अरबी भाषा में तैयार कराए गए हैं। इन्हें सत्यापन के लिए इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय भेजा गया है। कानून के तहत उसी अदालत से सत्यापन जरूरी है, जहां आरोपी के खिलाफ चालान पेश हुआ है।

डीआईजी राहुल लोढ़ा के मुताबिक अदालत से सत्यापन और मंजूरी मिलने के बाद अगले 15 दिनों में पूरी फाइल दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय भेजी जाएगी। दस्तावेज राज्य स्तरीय प्रक्रिया से गुजरकर केंद्रीय गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के जरिए यूएई के प्राधिकरण या अदालत तक पहुंचेंगे। वहां प्रत्यर्पण पर कानूनी प्रक्रिया होगी। भारत और यूएई के बीच 1999 से प्रत्यर्पण संधि लागू है। इसके तहत निर्धारित शर्तों के अधीन आरोपियों के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में एसटीएफ अब तक करीब 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

एसटीएफ के मुताबिक लविश के खिलाफ दर्ज एफआईआर, केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज मूल रूप से हिंदी में हैं। प्रत्यर्पण की फाइल यूएई की कानूनी प्रक्रिया में पेश की जानी है, इसलिए दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद कराया गया है। साथ ही अंग्रेजी भाषा में भी कॉपी तैयार कर ली गई है। इसमें एफआईआर, केस डायरी, आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य, अदालत से संबंधित दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं।

एसटीएफ ने पहले लविश के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी करवाया था। एसटीएफ ने बताया कि ब्लू नोटिस का मकसद किसी व्यक्ति की पहचान, लोकेशन या गतिविधियों से जुड़ी जानकारी जुटाना होता है। इसके बाद रेड नोटिस जारी कराया गया। रेड नोटिस किसी वांछित व्यक्ति को दुनिया भर में तलाशने और प्रत्यर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध होता है। हालांकि, रेड नोटिस खुद अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है और संबंधित देश अपने कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई करता है। दुबई में दाखिल हुआ पर बाहर नहीं निकला ब्लू नोटिस के बाद एसटीएफ को मिले इनपुट में सामने आया कि लविश अपने पासपोर्ट के जरिए दुबई में दाखिल हुआ था, लेकिन उसके बाद उसके बाहर निकलने का रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी आधार पर जांच एजेंसी ने उसके दुबई में होने की पुष्टि की। अब एसटीएफ का टारगेट उसकी लोकेशन पता करने से आगे बढ़कर उसे भारतीय न्यायिक प्रक्रिया के सामने लाना है।

रीवा-शहडोल समेत 11 जिलों में भारी बारिश, एमपी के पूर्वी हिस्से में फिर स्ट्रॉन्ग सिस्टम

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

मप्र में बारिश से जलस्रोत लबालब हो गए हैं। भोपाल का बड़ा तालाब छलकने को तैयार है। शुजालपुर में नेवज-जमधड़ नदी में जल प्रवाह जारी है। शहडोल में बाणसागर डैम के 6 गेट खोले गए हैं। -Dainik Bhaskar

MP में बारिश से जलस्रोत लबालब हो गए हैं। भोपाल का बड़ा तालाब छलकने को तैयार है। शुजालपुर में नेवज-जमधड़ नदी में जल प्रवाह जारी है। शहडोल में बाणसागर डैम के 6 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में फिर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है। शहडोल के बाणसागर डैम के रविवार को गेट खोल दिए गए। सिंगरौली में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई तो मंडला, चित्रकूट (सतना) में बाढ़ के बाद आफत खड़ी हो गई।

नदियों का उफान जरूर कम हुआ, लेकिन बर्बादी का मंजर देखने को मिला। देर रात तक कई जिलों में बारिश का दौर चला। बाढ़ प्रभावित सतना ने में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है।

सोमवार को भी पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इनमें रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट शामिल हैं।

वहीं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, पांढुर्णा, सतना, सिंगरौली, उमरिया, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री चित्रकूट पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया- रविवार को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी करीब 30 फीट उफान पर रही। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव में रामघाट का बड़ा पुल बह गया। घरों और सड़कों पर मिट्टी, कचरा और कीचड़ जमा हो गया।

सीएम मोहन यादव चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। आश्रय स्थल में प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। सीएम ने चित्रकूट में अतिक्रमण को भी बाढ़ की संभावित वजह माना।

वहीं, शहडोल का बाणसागर डैम भी लबालब हो चुका है। पानी की आवक 808.64 क्यूमेक्स थी, जो 12 घंटे में बढ़कर 2677.29 क्यूमेक्स हो गई। पिछले साल की तुलना में इस बार जलस्तर 13 सेंटीमीटर अधिक है। दोपहर 12 बजे डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने सितंबर की शुरुआती 3 दिन तक कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें सीधी, उमरिया, मंडला, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम समेत कई जिले शामिल हैं। यानी, 24 घंटे के अंदर यहां 4 से 8 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है।

लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के डैमों की स्थिति सुधरी है। अधिकांश डैम में 70 प्रतिशत तक पानी आ गया है। कुछ डैम के गेट तो खोल दिए गए हैं। इंदौर और उज्जैन संभाग के बांधों की हालत ठीक नहीं है।

भोपाल के बड़ा तालाब में पानी का लेवल 1666.50 फीट तक पहुंच गया है। अब यह सिर्फ 0.30 फीट ही खाली है। बड़ा तालाब फुल भरने के बाद भदभदा डैम के गेट खुलेंगे। यहां से छोड़ा जाने वाला पानी कलियासोत डैम में पहुंचेगा और इसमें भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा।

IMD (मौसम केंद्र) की माने तो प्रदेश में अब तक 700 मिमी यानी, 27.2 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि, यह अब तक की सामान्य बारिश 30.4 इंच (772.3 मिमी) की तुलना में 3.2 इंच कम है। वहीं, ओवरऑल 9 प्रतिशत कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से में 5% और पश्चिमी हिस्से में औसत से 12% बारिश कम हुई है।

प्रदेश के पूर्वी हिस्से- जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में 19% तक कम बारिश हुई है। बालाघाट, छतरपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सिवनी, टीकमगढ़, डिंडौरी, निवाड़ी में 1% से 50% तक कम बारिश हुई है।

वहीं, पश्चिमी हिस्से के आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, दतिया, देवास, धार, हरदा, इंदौर, झाबुआ, मुरैना, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, बड़वानी, खंडवा, रायसेन, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा में औसत से 1% से 51% कम पानी गिरा है।

IMD की माने तो अनूपपुर, निवाड़ी, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, गुना, ग्वालियर, खरगोन, राजगढ़ और शिवपुरी में ही औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

भोपाल में आज से सीलिंग की कार्रवाई, रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल एक्टिविटी... पुलिस की मौजूदगी में सील करेंगे प्रतिष्ठान

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

भोपाल के रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी करने पर सोमवार से सीलिंग की कार्रवाई शुरू होगी। नगर निगम की टीम भारी अमले और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करेगी। रविवार को प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे के नोटिस चस्पा किए गए हैं।

नगर निगम ने 26 अगस्त तक कुल 8264 नोटिस जारी किए थे। इसके बाद नोटिस का परीक्षण किया। बीच में वार्ड-58 के गौतम नगर स्थित रेसीडेंसियल बिल्डिंग में संचालित होटल को सील कर दिया गया। रविवार को 24 घंटे के नोटिस दिए गए और सोमवार से कार्रवाई शुरू की जाएगी। छह जगहों पर होगी कार्रवाई कार्रवाई में हंगामे की स्थिति को देखते हुए मिसरोद, हबीबगंज, रातीबढ़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग और कोलार थाना पुलिस थाने का बल तैनात किया जाएगा। सोमवार को छह जगहों पर कार्रवाई होगी।

यह है मामला- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश (स्टे ऑर्डर) निरस्त कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

इस दौरान नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना है। इसके चलते ही नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, पिछले चार दिन से व्यापारियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। अफसरों का कहना है कि नोटिस देने के बाद परीक्षण किया जा रहा है। कारोबारियों में दहशत नए सर्वे में भवन से जुड़े दूसरे उल्लंघनों की भी जांच की जा रही है। अर्बन प्लानिंग के विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि समय पर मास्टर प्लान आता तो रहवासियों और कारोबारियों के सामने यह स्थिति नहीं खड़ी होती। रहवासी और व्यावसायिक इलाके अलग-अलग चिह्नित बनाए जाते। सख्ती के बाद शहर के उन इलाकों के कारोबारियों में दहशत है, जो रहवासी इमारतों में दुकानें चला रहे हैं। अवधपुरी, अयोध्या बायपास, गौतम नगर, अशोका गार्डन, लालघाटी समेत जैसे इलाकों में दुकानदार नोटिस के बाद कमर्शियल इलाकों में दुकानें तलाश रहे हैं।

मुख्य मार्गों से सर्वे, नदी-तालाब किनारे भी जांच निगम ने मुख्य मार्गों के दोनों ओर और उनसे जुड़ी गलियों में सर्वे शुरू किया है। नदी-तालाब किनारे, ग्रीन बेल्ट, बफर जोन और कैचमेंट एरिया में बने भवन प्राथमिकता से जांचे जाएंगे। अवैध मैरिज गार्डन को भी नोटिस दिए जाएंगे।

गतांक से आगेः लोक कल्याण हेतु दादाजी का अवतरण

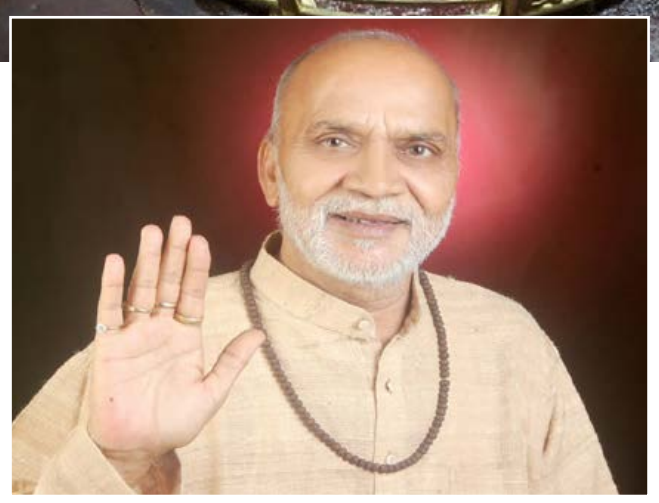

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

श्री दादाजी गुरुदेव का दिव्य वचनामृत श्री दादाजी गुरुदेव ने बताया कि सनातन धर्म में भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। इन पावन धामों में श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तिभाव, तपस्या, धैर्य और अटूट विश्वास की दिव्य गाथा से जुड़ा हुआ है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के वेरुल (एलोरा) में स्थित है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार, घुश्मा नामक धर्मपरायण स्त्री भगवान शिव की अनन्य उपासिका थीं। वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करतीं, विधिपूर्वक उनका पूजन करतीं और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए उनका विसर्जन करती थीं। उनकी साधना में पूर्ण समर्पण और निष्काम भक्ति का भाव था। समय के साथ उनके जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आईं। उनके पुत्र के साथ भी अत्यंत पीड़ादायक घटना हुई, किंतु घुश्मा का विश्वास महादेव के प्रति तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने आराध्य की पूजा को निरंतर बनाए रखा। उनका हृदय भगवान शिव की कृपा पर पूर्ण विश्वास से भरा था। उनकी अटूट साधना और निष्कपट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुश्मा के पुत्र को जीवन प्रदान किया और भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। घुश्मा ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि प्रार्थना की कि भगवान शिव इसी स्थान पर सदैव भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान रहें। भक्त की भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हुए। इसी कारण यह पावन धाम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री दादाजी गुरुदेव ने बताया कि इस कथा का सार केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, ईश्वर के प्रति विश्वास अडिग रखना, मन में क्षमा का भाव रखना और अपने सुख से पहले लोककल्याण की कामना करना ही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यह संदेश देता है कि जब श्रद्धा निष्कपट हो, विश्वास अटल हो और हृदय में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, तब ईश्वर की कृपा जीवन में आशा और प्रकाश का संचार करती है। इसी सनातन आध्यात्मिक परंपरा में श्री दादाजी गुरुदेव का लोक कल्याणकारी संदेश भी मानव मात्र को श्रद्धा, सेवा, सद्भाव, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महादेव की कृपा समस्त प्राणियों पर बनी रहे, सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सद्बुद्धि का प्रकाश हो तथा विश्व का कल्याण हो इसी मंगल भावना के साथ।

बीएचईएल में राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

बीएचईएल में राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु हिन्दी मास, 2026 के अंतर्गत गत दिवस सभी वर्गों के लिए हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उत्पादकता, गुणता, हिन्दी, प्रबंधन एवं सारगर्भित मौलिक रचनाओं को समाहित किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि हेमराम पटेल, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है जो हमारी शान है। उन्होंने कहाकि कविता का संबंध दिल से होता है। कविता दिल से निकल कर सीधे दिल तक पहुँचती है। कविता पाठ तनाव निवारक की तरह कार्य करता है। प्रतिभागी कविता गद्य एवं पद्य दोनों में व्यक्त करें और कविता का प्रस्तुतीकरण ऐसा हो जो दिल के भावों को छू ले। कार्यक्रम का संचालन पूनम साहू, प्रबंधक (मा. सं.-राजभाषा एवं सीआईएसएफ समन्वयक) ने किया। इस प्रतियोगिता में 18 रचनाओं का पाठ किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पीके झा, अपर महाप्रबंधक (सीएमएम) ने कहा कि सभी में केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं शब्दों को गढ़ने का भी अच्छा ज्ञान है। सभी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बीएचईएल का भविष्य उज्जवल है। इस अवसर पर प्रतियोगिता की दूसरी निर्णायक नीतू धमीजा ने कहा कि आज इस प्रतियोगिता में आकर आनंद आ गया। कविताएं सुनकर अचरज के साथ हर्ष भी हुआ कि संस्थान में योग्यता की कमी नहीं है।

दादाजी धाम में गूंजेगा श्रीकृष्ण नाम, जन्माष्टमी पर भजन, रासलीला और कीर्तन से सजेगी भक्तिमय रात

4 सितंबर शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, श्री दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव एवं मीराबाई प्राणप्रतिष्ठा दिवस का भव्य आयोजन

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

पटेल नगर स्थित जागृत एवं दर्शनीय तीर्थ स्थल दादाजी धाम मंदिर, रायसेन रोड, भोपाल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, श्री श्री 1008 श्री दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव एवं मीराबाई प्राणप्रतिष्ठा दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक में श्री श्री 1008 श्री दादाजी गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी, मंदिर व्यवस्था समिति के सदस्य एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन नामदेव ने बताया कि 4 सितंबर को दादाजी धाम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, श्री दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव एवं मीराबाई प्राणप्रतिष्ठा दिवस श्रद्धा, भक्ति एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाने की तैयारियां की जा रही हैं।

महोत्सव के अवसर पर लड्डू गोपाल, भगवान श्रीकृष्ण एवं राधारानी का विशेष श्रृंगार सुंदर वस्त्रों एवं आकर्षक आभूषणों से किया जाएगा। मंदिर परिसर में मनमोहक विद्युत सज्जा की जाएगी। जन्माष्टमी पर नन्हे-मुन्ने बच्चे भगवान श्रीकृष्ण एवं राधारानी के मनोहारी स्वरूप में सजकर उत्सव की शोभा बढ़ाएंगे।

दादाजी धाम मंदिर में शाम 7:30 बजे से भजन संध्या, रासलीला एवं संकीर्तन का भक्तिमय आयोजन होगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में भाव-विभोर होंगे। भगवान को धनिया पंजीरी तथा माखन-मिश्री का भोग अर्पित कर प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा।

रात्रि में भगवान श्रीकृष्ण के 12 बजे जन्मोत्सव के पश्चात रात्रि 12:05 बजे श्री दादाजी गुरुदेव का जन्मोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके बाद आरती संपन्न होगी तथा श्रद्धालुओं को महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा।

आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर मंदिर के पट पूरे दिन श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहेंगे।

ट्रस्ट अध्यक्ष शिवरतन नामदेव ने सभी श्रद्धालुओं से परिवार सहित दादाजी धाम मंदिर पहुंचकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं श्री दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव के पावन अवसर पर सहभागी बनने तथा भगवान श्रीकृष्ण एवं श्री दादाजी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का आग्रह किया है।

किन्नर समाज ने धूमधाम से मनाया भुजरिया पर्व, देश में खुशहाली और अच्छी बारिश की कामना

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

किन्नर समाज ने वर्षों पुरानी परंपरा के तहत रविवार को भुजरिया पर्व धूमधाम से मनाया। किन्नर समुदाय की प्रमुख काजल गुरु के नेतृत्व में भुजरियों की शोभायात्रा निकाली गई। जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुफा मंदिर पहुंचा, जहां विधि-विधान से भुजरियां भगवान को अर्पित की गईं। काजल गुरु ने बताया कि भोपाल में किन्नर समाज लंबे समय से भुजरिया पर्व को परंपरा के रूप में मनाता आ रहा है। समाज के लोग इस पर्व को अच्छी बारिश, सुख-समृद्धि और देश की खुशहाली से जोड़कर देखते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हर वर्ष भुजरियों की शोभायात्रा निकाली जाती है। इस बार भी बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग जुलूस में शामिल हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभायात्रा गुफा मंदिर पहुंची। यहां भुजरियों को भगवान को अर्पित कर पूजा-अर्चना की गई। समाज के लोगों ने देश में शांति और समृद्धि के साथ अच्छी बारिश की कामना की। आयोजन के दौरान पारंपरिक धार्मिक माहौल नजर आया। काजल गुरु ने बताया कि इस बार भुजरिया पर्व को बॉलीवुड थीम से अलग हटकर धार्मिक थीम पर मनाया गया। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज अपनी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

विविध कला विकास समिति रामलीला पिपलानी 67वां वर्ष होने पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई

दैनिक कारखाने का सफर। भोपाल

विविध कला विकास समिति रामलीला पिपलानी 67 वा वर्ष होने पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर रामलीला समिति के फाउंडर मेंबर श्याम सुंदर, अध्यक्ष रूपेश तैलंग, महासचिव आर,एस अरोरा, वरिष्ट उपाध्यक्ष शिव प्रसाद साहू उपस्थित थे। रामलीला कलाकार लक्ष्मण पाटिल, लोकेश मौर्य,मयंक सिंह, हिम्मत राव पाटिल, दीपेंद्र कौशिक उपस्थित थे !रविवार को बैठक मे नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें वाल्मीक सोनी, विकास तिवारी सह कोषाध्यक्ष सर्व सम्मति से मनोनीत किया गया गया। कार्यकारिणी की बैठक में विगत वर्ष के आय - व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। समिति प्रवक्ता अतुल मालवीय के अनुसार इस वर्ष रामलीला का भव्य मंचन डिजिटल प्रकाश व्यवस्था के साथ किया जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था में बढ़ती अव्यवस्था!

आजादी के आठ दशक पूरे हो गए हैं। एक पीढ़ी ने इस दौरान हुए परिवर्तन को देखा है और उसमें भागीदारी की है। उपलब्धियों तथा कमियों का विश्लेषण भी किया है। वे आज की 'जेन जी' की भाषा से भले ही अनभिज्ञ हों, मगर अनुभव उनके पास है, जिसको यदि सही ढंग से समझ लिया जाए, तो भावी पीढ़ी के लिए यह उपयोगी ही होगा। ये लोग जब महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में थे (यानी 1947-67 के दौरान), तब इनका प्रश्नपत्र-लीक, नकल माफिया और कोचिंग संस्थान जैसे शब्दों से कोई परिचय नहीं था। उन्हें शिक्षकों, परीक्षकों और लोक सेवा आयोग पर पूरा विश्वास था। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह था कि जनप्रतिनिधियों की निष्ठा पर लोगों को भरोसा था। उन्हें मूल्य-आधारित जीवन जीने का अनुभव था। मगर आज ऐसा नहीं है, युवाओं के लिए अनुकरणीय व्यक्तित्व ढूंढ़ पाना कठिन है। आज का हर तरुण और युवा अपने भविष्य को लेकर तनाव में है। परिवार और माता-पिता उनसे भी अधिक चिंतित हैं। स्वतंत्रता के बाद देश की आबादी बढ़ी। राज्य सरकारों ने शिक्षा के लिए आवश्यक आबंटन कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। ऐसे में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिला। देश में शिक्षा उद्योग बन गई, जिसमें लाभांश सुनिश्चित था। चूंकि साक्षरता बढ़ाना आवश्यक था, इसलिए स्कूलों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थी भी बढ़े, लेकिन गुणवत्ता घटती चली गई। इससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति यह बनी कि समाज में नैतिकता का ह्रास हुआ और मानवीय मूल्यों का महत्त्व भी कमजोर होता गया। आज युवाओं को प्रश्नपत्र लीक और दोबारा परीक्षाओं का बोझ एवं तनाव झेलना पड़ रहा है। जंतर मंतर और रांची में प्रदर्शन उनके इसी गुस्से का द्योतक है। यह परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों का ही नतीजा है कि कुछ विद्यार्थी तनाव के बीच अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। ऐसी स्थितियों को निर्मित करने वाले अपराधी पढ़े-लिखे होते हैं, वे व्यवस्था को जानते हैं और उसे चलाने वालों में से कुछ को चिह्नित कर उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा संस्थाएं और व्यवस्था उस सर्वकालिक मूल्य-बोध से दूर हो गई हैं, जिसमें उनका घोषित उद्देश्य 'व्यक्ति से व्यक्तित्व' निर्माण होता है। यदि इसे बदलना है, तो शिक्षा व्यवस्था के बाहर के परिदृश्य पर भी निगाह डालनी होगी और उसका विश्लेषण करना होगा।

बीसवीं सदी ने साम्राज्यवाद का सूरज अस्त होते देखा। वे सभी प्रबुद्ध व्यक्ति और देश जो विश्व शांति और 'अब और युद्ध नहीं' के पक्षधर थे, वे जानते थे कि साम्राज्यवाद मनुष्य की कुछ अंतर्निहित प्रवृत्तियों का परिणाम होता है, जिनमें हर कोई अन्य से अधिक श्रेष्ठ, समृद्ध और अधिकार संपन्न दिखना चाहता है। इसका उदाहरण आज का अमेरिका है, जो वेनेजुएला, कनाडा और ग्रीनलैंड को आत्मसात करना चाहता है। द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद यह चर्चा प्रारंभ हुई कि भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे। भारत इसे बहुत पहले से समझ चुका था कि 'ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है'। प्राचीन भारत के मनीषी इसे जानते-समझते थे, उनकी ज्ञान-साधना का लक्ष्य सत्य की खोज था। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान अर्जन में जो तेजी आई है, उसमें और प्राचीन भारतीय ज्ञान अर्जन परंपरा में एक बहुत बड़ा अंतर है। वैसे यह अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि ज्ञान के साथ बुद्धि, विवेक और मानवीय संवेदना का समन्वय आवश्यक है। यह भारत का उत्तरदायित्व बनता है कि सहिष्णुता के अपने इतिहास को याद कर वह वैश्विक स्तर पर इस विचार को स्थापित करे, लेकिन भारत इस उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकेगा, जब उसकी अपनी शिक्षा व्यवस्था और उसका प्रबंधन अनुकरणीय स्तर पर आ सके। मगर आज ऐसा दिखाई नहीं देता है। शिक्षा नीतियां कुछ भी कहें, तथ्य यह है कि गुणवत्ता का मानक आज भी पश्चिमी देशों की व्यवस्था तथा विषय वस्तु तक ही सीमित है। विश्व के जिन देशों के लिए भारत केवल एक बाजार है, वह हमारी शिक्षा व्यवस्था को रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? भारत भी पश्चिम के देशों की नकल कर यदि अपनी शिक्षा की विषयवस्तु और व्यवस्था बनाता है, तो वह केवल डिग्री ही दे सकता है, भारतीयता नहीं। शिक्षा में मानव-तत्त्व की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, लेकिन वही कमजोर हो रहा है। कृत्रिम मेधा शिक्षा और उसके प्रबंधन को नए-नए स्तरों पर ले जा रही है। भारत को भी उसमें अग्रणी होना होगा, लेकिन भारतीय तत्त्व उसमें खो न जाए, इसका ध्यान भी रखना होगा। अब यह सिद्ध हो चुका है कि विश्व में मान-सम्मान उसी देश को प्राप्त हो सकेगा, जिसकी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता, उत्कृष्टता और मानवीय तत्त्व से परिपूर्ण होगी। भारत की शिक्षा नीति में ऐसे तत्त्व उपलब्ध हैं, जो उसे भविष्योन्मुखी बना सकते हैं। मगर इसके लिए हर स्तर पर अकादमिक नेतृत्व की उपस्थिति आवश्यक है। जिन लोगों ने आजादी के बाद के तीन दशकों तक की शिक्षा व्यवस्था देखी है, वे जानते हैं कि उस समय तक शिक्षा संस्थाओं का नेतृत्व नौकरशाहों के हाथ में नहीं था, जैसा कि आज है। देश में आज एक लाख से अधिक स्कूल केवल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। पिछले दो वर्षों में सरकारी स्कूलों में नामांकन 86 लाख तक घटा है, जबकि निजी स्कूलों में इसी दौरान नामांकन 88 लाख बढ़ा है। केवल कागजों में शिक्षक-छात्र अनुपात के महत्त्व को दर्शाना और व्यावहारिकता में उससे आंखें चुरा लेना, हर उस बच्चे के साथ अन्याय है जो इस प्रकार की व्यवस्था में पढ़ने के लिए मजबूर है। ये बच्चे उन परिवारों से आते हैं, जिन्हें शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता है और वे विकास की धारा में अंतिम छोर पर खड़े हैं। इनके भविष्य निर्माण के लिए चाहिए नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व, जिनमें भारत की विविधताओं की समझ हो, उसके प्रति सम्मान की भावना हो। जिनके पास देश के भविष्य को संवारने का आत्मविश्वास और इच्छाशक्ति हो। ऐसे लोगों की उपस्थिति प्राथमिक पाठशाला से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक सुनिश्चित करनी होगी।

विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा!

सरकारें जब विकास परियोजनाओं का खाका खींचती हैं, तो उसके पीछे देश को शिखर पर ले जाने की छटपटाहट होती है। मगर इस विकास यात्रा का एक स्याह और मार्मिक पहलू भी है। इन तमाम परियोजनाओं की बुनियाद 'भूमि' पर ही टिकी है। कृषि-प्रधान भारत में किसी किसान या आदिवासी के लिए जमीन महज मिट्टी या 'गाटा संख्या' नहीं, बल्कि उसकी अस्मिता, पुरखों की धरोहर और पीढ़ियों की आजीविका का अटूट सहारा है। ऐसे में लोकतंत्र के सामने यक्ष प्रश्न है- विकास की रफ्तार और विस्थापन के दर्द में मानवीय संतुलन कैसे सधे? क्या राष्ट्र-निर्माण के यज्ञ में आहुति हमेशा सबसे कमजोर वर्ग ही देगा, या हम कोई ऐसा समावेशी रास्ता निकाल सकते हैं, जहां प्रगति की कीमत किसी की बेदखली न हो?

किसानों को 1894 के औपनिवेशिक कानून से मुक्ति दिलाने के लिए 2013 में 'भूमि अधिग्रहण अधिनियम' लाया गया, जो एक जनवरी 2014 से लागू हुआ। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य के आधार पर अधिक मुआवजे, 'सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन' और पुनर्वास के साथ निजी परियोजनाओं में 80 फीसद तथा पीपीपी परियोजनाओं में 70 फीसद प्रभावित परिवारों की सहमति को अनिवार्य किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकार को भी महत्त्वपूर्ण सुरक्षा दी, लेकिन जमीनी हकीकत कई मामलों में इसके उलट दिखाई देती है।'सार्वजनिक उद्देश्य' और कानून में दिए गए आपातकालीन प्रावधानों के तहत कुछ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अलग हो सकती है। रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी विशेष परिस्थितियों के साथ-साथ कानून में निर्धारित अपवादों के कारण सहमति और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सामान्य प्रावधान हर मामले में समान रूप से लागू नहीं होते। भूमि के समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्यों, दोनों के स्तर पर कानून और नियमों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। विकास की इस तेज रफ्तार में 2013 के कानून की मानवीय भावना का प्रभावी क्रियान्वयन आज भी बड़ी चुनौती है। देश में विकास का भूगोल भले ही अलग हो, लेकिन अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी हर दिशा में एक समान है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और बिहार जैसे क्षेत्रों में लहलहाती बहुफसली कृषि भूमि एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ली जा रही है, जिससे छोटी जोत वाले किसानों के सामने आजीविका का संकट खड़ा होता है। वहीं, राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्य और पूर्वी भारत में कोयला तथा खनिजों का व्यापक खनन हुआ है, जिसने जंगलों और स्थानीय समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। पश्चिमी भारत में 'स्वच्छ ऊर्जा' के नाम पर 'मेगा सोलर पार्कों' को लेकर पशुपालकों के पारंपरिक चरागाहों के उपयोग पर भी विवाद सामने आए हैं। दक्षिण में आइटी गलियारे के लिए भूमि परिवर्तन और पूर्वोत्तर में जलविद्युत परियोजनाओं तथा सीमांत सड़कों के विस्तार ने स्थानीय समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण को लेकर बहस छेड़ दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में देश के 45.8 फीसद कामगार कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में लगे थे। वहीं, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, देश की लगभग 86 फीसद परिचालन भूमि जोत छोटे और सीमांत किसानों के पास थीं। इनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण केवल संपत्ति का सौदा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की आजीविका को प्रभावित करने वाला फैसला है। वित्तीय साक्षरता के अभाव में नकद मुआवजा 'मुट्ठी की रेत' साबित हो सकता है और किसान कुछ वर्षों में फिर आर्थिक संकट में फंस सकता है। वहीं, भूमिहीन मजदूर और बटाईदार पुनर्वास की प्रक्रिया से अक्सर पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ पाते। दूसरी ओर, कृषि भूमि पर कारपोरेट नियंत्रण का एक नया और परोक्ष स्वरूप भी दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों में 'भूमि बैंक' और दीर्घकालिक लीज जैसे माडल के जरिए औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिए बड़े भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, 'कान्ट्रैक्ट फार्मिंग' या अनुबंध खेती के जरिए उत्पादन से लेकर बाजार तक कारपोरेट भागीदारी बढ़ी है। ऐसे माडलों में पारदर्शिता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और भूमि-उपयोग के सामाजिक प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विकास की आड़ में बढ़ती यह प्रवृत्ति उस भविष्य की आशंका पैदा करती है, जहां स्वतंत्र अन्नदाता अपनी ही जमीन पर आर्थिक रूप से निर्भर मजदूर बनने को मजबूर हो सकता है।

आबादी में लगभग 8.6 फीसद होने के बावजूद, ऐतिहासिक अध्ययनों में विकास परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में आदिवासियों की हिस्सेदारी कई क्षेत्रों और अवधि में असंगत रूप से अधिक पाई गई है। उनके लिए 'जल-जंगल-जमीन' महज आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि उनकी आत्मा और सांस्कृतिक पहचान है। वनाधिकार कानून ग्राम सभाओं को वनाधिकारों की पहचान और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका देता है। इसके बावजूद कोयला खदानों, बड़े बांधों और अन्य परियोजनाओं के दौरान वनाधिकारों तथा ग्राम सभा की प्रक्रियाओं के पालन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। 2019-20 से 2023-24 के बीच 95,724.99 हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न गैर-वानिकी उपयोगों के लिए परिवर्तित कर देने को मंजूरी दी गई। कागजों पर किए गए 'प्रतिपूरक वनीकरण' की प्रक्रिया सदियों पुराने जंगलों के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र की तत्काल भरपाई नहीं कर सकती।

कंक्रीट के विस्तार से प्राकृतिक जल निकासी और स्थानीय पारिस्थितिकी पर भी दबाव बढ़ता है। 'प्रतिपूरक वनीकरण के बावजूद प्राचीन जंगलों के जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को रातों-रात पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र के 'थर्ड मुंबई' मेगा-सिटी से लेकर कर्नाटक के बिदादी तक, किसान भूमि अधिग्रहण और प्रस्तावित विकास माडल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

इन सुलगते आंदोलनों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के प्रश्न पर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया है कि मुआवजा महज एक यांत्रिक या सूत्रबद्ध प्रक्रिया नहीं हो सकता, बल्कि उसे समानता, न्याय और परिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और राज्य इसे मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता। इस दूरगामी संकट का हल विकास का पहिया रोकना नहीं, बल्कि प्रक्रिया को न्यायसंगत और मानवीय बनाना है। जबरन अधिग्रहण के बजाय पारदर्शी साझेदारी माडल ('लैंड पूलिंग') अपनाया जाए, जहां किसान मालिकाना हक न खोए और उसे नियमित आय मिले। माटी छूटने के बाद विस्थापित युवा अकुशल मजदूर न बनें, इसके लिए उन्हें युद्धस्तर पर कौशल विकास का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए। सबसे अहम, खाद्य सुरक्षा की कीमत पर उपजाऊ खेतों में कंक्रीट बोने के बजाय सरकार बुनियादी ढांचे के लिए बंजर और कम उपजाऊ भूमि को प्राथमिकता दे। विकास और मानवाधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। सच्ची प्रगति वह है, जो एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार के साथ-साथ कतार में खड़े आखिरी इंसान का भी हाथ थामकर चले। देश को आर्थिक उड़ान के लिए कारखानों की जितनी जरूरत है, उतनी ही दरकार अन्नदाता के चेहरे पर सुकून की भी है। चमकते बुनियादी ढांचे और लहलहाते खेतों के बीच का मानवीय संतुलन ही एक नए, न्यायपूर्ण और सशक्त भारत की मजबूत नींव रखेगा।

संकट में नेपाल के काम India ही आया

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने सिर्फ सैकड़ों जिंदगियां नहीं लील लीं, बल्कि हिमालयी क्षेत्र की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और पड़ोसी देशों के रिश्तों का एक बेहद महत्वपूर्ण आईना भी सामने रख दिया है। बुधवार को नेपाल-तिब्बत सीमा के आसपास ग्लेशियर के ढहने और उसके बाद मलबे के साथ आए भयावह जलप्रवाह ने रसुवा, नुवाकोट और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई। सड़कें, पुल, मकान और जलविद्युत परियोजनाएं बह गईं। इस आपदा ने नेपाल की बिजली व्यवस्था को भी ऐसा झटका दिया कि अब वही नेपाल, जो मानसून में भारत को बिजली बेचता है, जरूरत पड़ने पर भारत से बिजली मांग सकता है। यही इस त्रासदी का सबसे बड़ा विडंबनापूर्ण पहलू है। नेपाल की करीब 4,300 मेगावाट की स्थापित बिजली क्षमता में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी जलविद्युत की है। बाढ़ ने करीब 13 जलविद्युत संयंत्रों और एक सौर परियोजना को प्रभावित किया और लगभग 360 मेगावाट उत्पादन क्षमता पर असर पड़ा। भारत को बिजली देने वाला 14 मेगावाट का देविघाट संयंत्र भी इसकी चपेट में आया। 26 अगस्त को बाढ़ के दिन भारत नेपाल से एक समय में 963.4 मेगावाट तक बिजली ले रहा था, लेकिन अगले ही दिन

बिजली आपूर्ति लगभग आधी रह गई। और अब तस्वीर उलट सकती है। आमतौर पर गर्मियों में भारत नेपाल से बिजली खरीदता है और सर्दियों में, जब नेपाल की जलविद्युत उत्पादन क्षमता घटती है, भारत नेपाल को बिजली देता है। लेकिन इस बार आपदा ने परिस्थितियां ऐसी बना दी हैं कि मानसून के इसी मौसम में भारत को नेपाल की मदद के लिए बिजली निर्यात करनी पड़ सकती है। दोनों देशों के बीच पहले से ही 1,000 मेगावाट की आयात-निर्यात क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 1,400 मेगावाट से अधिक करने पर सहमति भी बन चुकी है। लेकिन बिजली से बड़ी कहानी भरोसे की है। आपदा तिब्बत से लगे इलाके में शुरू हुई। उपलब्ध वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार इसका संबंध ग्लेशियर के ढहने और भारी मलबे के नदी में आने से है। चीन ने यह आपदा पैदा की या नहीं, इसका जवाब तो वैज्ञानिक ही देंगे लेकिन आम लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि हिमालय के इस संवेदनशील भूभाग में सीमा के दोनों ओर होने वाली गतिविधियों, बुनियादी ढांचे और आपदा-प्रबंधन को लेकर भारत, नेपाल और चीन के बीच पारदर्शिता कितनी है? हालात इतने गंभीर थे कि तिब्बत की ओर एक नए 'बैरियर लेक' के बनने और उसके टूटने की आशंका ने नेपाल में फिर खतरे की घंटी बजा दी। इसी संकट में भारत और चीन के रवैये का फर्क नेपाल के सामने साफ दिखाई देता है। बाढ़ के कुछ ही घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और हरसंभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया। उसी रात भारतीय वायुसेना का C-130J विमान हिंडन से काठमांडू पहुंचा और 10 टन राहत सामग्री तथा जरूरी दवाइयां भेजी गईं। इसके बाद राहत सामग्री की कुल मात्रा 47 टन से अधिक हो गई। भारत ने 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन भी सक्रिय की। नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जनता जिस तरह भारत का शुक्रिया कर रहे हैं उससे उनका भारत के प्रति विश्वास भी परिलक्षित हो रहा है। देखा जाये तो यही अंतर है, मुसीबत में कौन आपके साथ खड़ा होता है और कौन सिर्फ सीमा के उस पार मौजूद रहता है। नेपाल के लिए यह समय किसी देश के पक्ष में राजनीतिक नारा लगाने का नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित को ठंडे दिमाग से देखने का है। भारत से नेपाल का रिश्ता सिर्फ बिजली खरीदने-बेचने का नहीं है। खुली सीमा, गहरे सामाजिक रिश्ते, व्यापार, रोजगार, धार्मिक यात्राएं और रोजमर्रा की मानवीय आवाजाही दोनों देशों को असाधारण रूप से जोड़ती है। जब नेपाल में संकट आया तो भारत ने इन रिश्तों को कागज पर नहीं, जमीन और आसमान पर साबित किया। शायद नेपाल को इस संकट में एक पुरानी बात नए सिरे से समझ आई होगी, दोस्त वही नहीं जो सामान्य दिनों में साथ दिखे, दोस्त वह है जो आपदा में सबसे पहले पहुंच जाए। और चीन के साथ संबंधों को लेकर भी काठमांडू को यह तय करना होगा कि रणनीतिक साझेदारी का अर्थ केवल बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और निवेश नहीं है। असली साझेदारी संकट के समय दिखाई देती है। भारत और चीन के बीच नेपाल को किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन नेपाल यह जरूर देख सकता है कि उसके लिए कौन-सा पड़ोसी भरोसे का स्थायी आधार है।

खेलों की उड़ान, विकसित भारत की पहचान!

राष्ट्रीय खेल दिवस केवल एक महान खिलाड़ी की स्मृति को नमन करने का अवसर नहीं, बल्कि राष्ट्र की खेल-चेतना को जगाने एवं खेल आयामों को नये शिखर देने का दिन है। 29 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिवस हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती से जुड़ा है। खेल किसी राष्ट्र की शक्ति का केवल प्रदर्शन नहीं होते, वे उसके आत्मविश्वास, अनुशासन, सामूहिकता और वैश्विक प्रतिष्ठा के दर्पण भी होते हैं। आज जब भारत 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तब खेलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा से जोड़ना समय की अनिवार्यता है। स्वस्थ नागरिक, अनुशासित युवा, विश्वस्तरीय खिलाड़ी और खेल-संस्कृति से संपन्न समाज-ये विकसित भारत की आधारशिलाएं हैं। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के ऐसे जादूगर थे, जिन्होंने अपनी स्टिक से केवल गोल नहीं किए, बल्कि दुनिया के खेल मानचित्र पर भारत की पहचान अंकित की। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की स्वर्णिम सफलता में उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। उनके खेल में कौशल के साथ राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समर्पण का अद्भुत समन्वय था। उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना वास्तव में उस खेल-दर्शन को याद करना है जिसमें प्रतिभा से बड़ा परिश्रम और व्यक्तिगत उपलब्धि से बड़ा राष्ट्र का गौरव होता है। ध्यानचंद की विरासत आज के खिलाड़ियों को यह संदेश देती है कि खेल का अंतिम लक्ष्य केवल पदक नहीं, बल्कि देश के लिए सम्मान अर्जित करना है। निश्चित तौर पर खेल अब मनोरंजन नहीं, राष्ट्रीय शक्ति हैं। एक समय भारत में खेलों को पढ़ाई या रोजगार के विकल्प के रूप में गंभीरता से नहीं देखा जाता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। क्रिकेट से आगे बढ़कर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, हॉकी, टेबल टेनिस, तीरंदाजी, शतरंज और अनेक अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण जीतकर भारतीय युवाओं को बताया कि ट्रैक और फील्ड में भी भारत विश्व विजेता बन सकता है। पी. वी. सिंधु ने बैडमिंटन में लगातार दो ओलंपिक पदक जीतकर नई पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित किया। मनु भाकर, डी. गुकेश, मीराबाई चानू, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, अवनि लेखरा, हरमनप्रीत सिंह और अनेक खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में भारतीय प्रतिभा की

व्यापकता सिद्ध की है। यह बदलाव किसी एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि बदलती हुई राष्ट्रीय खेल-संस्कृति का संकेत है। टोक्यो 2020 में भारत ने सात पदक जीते और पेरिस 2024 में छह पदक हासिल किए। पदकों की संख्या भले ही अभी विकसित खेल राष्ट्रों के बराबर न हो, लेकिन भारतीय खेलों की चौड़ाई और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता लगातार बढ़ी है। पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन तो विशेष रूप से प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने यह मिथक तोड़ा है कि शारीरिक सीमाएं सफलता की सीमा निर्धारित करती हैं। भारत की वास्तविक उपलब्धि केवल पदकों में नहीं है। आज छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से निकलने वाले युवा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह खेलों के लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों को राष्ट्रीय विकास और युवा सशक्तीकरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सामने रखा है। 'खेलो इंडिया' जैसी पहल ने विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान तथा खेल अवसंरचना के विकास को गति दी है। टॉप्स-टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से संभावित ओलंपिक पदक विजेताओं को लक्षित सहायता दी जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और विश्वविद्यालय खेलों ने युवाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध कराया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, पोषण, विदेशी प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, वैज्ञानिक सहयोग और आर्थिक सहायता पर बढ़ता ध्यान इस बात का संकेत है कि खेल नीति अब केवल प्रतियोगिता आयोजित करने तक सीमित नहीं है। प्रतिभा की खोज से लेकर उसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी बनाने तक एक समग्र खेल-परिसंस्था तैयार करने की कोशिश हो रही है। जब हम 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएंगे, तब विकसित भारत की तस्वीर केवल ऊंची जीडीपी, आधुनिक सड़कों, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय शहरों से पूरी नहीं होगी। विकसित भारत का वास्तविक अर्थ होगा-स्वस्थ नागरिक, ऊर्जावान युवा, मानसिक रूप से मजबूत समाज और विश्व मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा राष्ट्र। इस लक्ष्य में खेलों की भूमिका निर्णायक है। खेल युवाओं को नशे, निष्क्रिय जीवनशैली और दिशाहीनता से दूर रख सकते हैं। वे समयबद्धता, लक्ष्य-निर्धारण, हार को स्वीकार कर पुनः प्रयास करने की क्षमता और नेतृत्व सिखाते हैं। खेल मैदान लोकतंत्र की तरह हैं-यहां प्रदर्शन, अनुशासन और योग्यता ही निर्णायक होते हैं। आज देश में फिटनेस और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक विकास तभी सार्थक होगा जब उसकी ऊर्जा स्वस्थ मानव संसाधन में परिवर्तित हो। फिट भारत ही उत्पादक भारत और शक्तिशाली भारत का आधार बन सकता है। खेलों की एक और बड़ी शक्ति है-वे सीमाओं के पार संवाद स्थापित करते हैं। मैदान में प्रतिद्वंद्वी देश आमने-सामने होते हैं, लेकिन खेल के बाद वही खिलाड़ी एक-दूसरे के अनुभव, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को समझते हैं। ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं देशों के बीच संवाद और सद्भाव का माध्यम बनती हैं। भारत की खेल उपलब्धियां उसकी सॉफ्ट पावर को मजबूत करती हैं। जब भारतीय खिलाड़ी विश्व मंच पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गूंजता है, तो करोड़ों भारतीयों में एक साथ गर्व और एकता की अनुभूति पैदा होती है। खेलों ने भारत को दुनिया के सामने एक युवा, आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उपलब्धियों के बावजूद भारत को खेल महाशक्ति बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। गांव-गांव तक अच्छे मैदान, प्रशिक्षित कोच, खेल विज्ञान केंद्र, पोषण सुविधाएं और आधुनिक उपकरण पहुंचाने होंगे। खेलों को केवल कुछ लोकप्रिय खेलों तक सीमित रखने के बजाय ओलंपिक और पारंपरिक भारतीय खेलों की व्यापक श्रृंखला को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों में खेल का समय बढ़ाना, प्रतिभाशाली बच्चों की प्रारंभिक उम्र में पहचान करना और उन्हें शिक्षा के साथ खेल का समान अवसर देना आवश्यक है। महिला खिलाड़ियों, दिव्यांग खिलाड़ियों और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाओं के लिए विशेष अवसर और सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन मानसिकता में होना चाहिए। खेल में हार असफलता नहीं, अगली जीत की तैयारी है। यह भावना यदि शिक्षा और जीवन में भी उतर जाए तो भारत की युवा शक्ति असाधारण परिणाम दे सकती है। खेल केवल पदक नहीं देते, वे रोजगार और अर्थव्यवस्था भी बनाते हैं। स्टेडियम, खेल उपकरण, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, फिटनेस उद्योग, खेल प्रसारण, पर्यटन, कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन और डेटा एनालिटिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो रहे हैं। भारत में खेल-आधारित स्टार्टअप और तकनीकी नवाचारों की संभावनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। अर्थात खेलों में निवेश केवल खिलाड़ियों पर खर्च नहीं, बल्कि भविष्य की मानव पूंजी और नई अर्थव्यवस्था में निवेश है। इसलिये राष्ट्रीय खेल दिवस हमें एक महत्वपूर्ण संकल्प लेने का अवसर देता है-हर बच्चा खेले, हर युवा फिट रहे और हर प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिले। हमें ऐसी खेल संस्कृति विकसित करनी होगी जिसमें अभिभावक खेल को समय की बर्बादी न समझें, विद्यालय खेल को अतिरिक्त गतिविधि न मानें और समाज खिलाड़ी को केवल पदक जीतने के बाद सम्मान न दे। 2047 का विकसित भारत यदि दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहता है तो उसे खेलों में भी अग्रणी राष्ट्र बनना होगा। आर्थिक शक्ति और खेल शक्ति एक-दूसरे की पूरक हैं। जिस देश के युवा मैदान में लक्ष्य साधना सीखते हैं, वे जीवन में भी बड़े लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस इसलिए केवल ध्यानचंद को श्रद्धांजलि का दिवस नहीं; यह भारत की युवा शक्ति को जगाने, खेल को जीवन का हिस्सा बनाने और विकसित भारत के निर्माण में खेलों को राष्ट्रीय अभियान बनाने का दिवस है। आज आवश्यकता है कि हम ध्यानचंद की खेल-प्रतिभा, नीरज की दृढ़ता, सिंधु के संघर्ष, मनु भाकर के आत्मविश्वास और हमारे हजारों उभरते खिलाड़ियों के सपनों को एक राष्ट्रीय संकल्प में बदलें। 2047 का भारत केवल आर्थिक रूप से समृद्ध न हो, बल्कि शरीर से स्वस्थ, मन से मजबूत, चरित्र से अनुशासित और खेल के मैदान में विश्वविजयी भारत बने-यही राष्ट्रीय खेल दिवस का सबसे सार्थक संदेश है।

- ललित गर्ग

अब उज्बेकिस्तान में भी चलेगा भारतीय UPI, PM मोदी के दौरे में 11 ऐतिहासिक समझौते

एजेंसी ताशकंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के संबंधों को नई ऊंचाई देते हुए दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने का फैसला किया है। इस दौरान संस्कृति, आयुर्वेद, खनिज संसाधन, पर्यटन, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त और वैज्ञानिक शोध समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों और अन्य पहलों की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी यात्रा के परिणामों के मुताबिक, दोनों देशों ने 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर समझौता किया है। इसके तहत दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क और आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।

भारत उज्बेकिस्तान के प्राचीन बौद्ध स्थलों फयाज टीपा और करा टीपा के संरक्षण और पुनरुद्धार में भी सहयोग करेगा। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल उज्बेकिस्तान के तेरमेज क्षेत्र में स्थित हैं। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय और उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत एजेंसी के बीच लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच भी सहयोग का समझौता हुआ है। वहीं, आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी एमओयू किया गया।

भारत के खान मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के खनन उद्योग एवं भूविज्ञान मंत्रालय के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। पर्यटन के क्षेत्र में 2026-28 के लिए साझेदारी कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस और उज्बेकिस्तान की डिप्लोमैटिक अकादमी के बीच सहयोग का समझौता हुआ है। दोनों देशों के वित्त मंत्रालयों के बीच आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने के लिए भी एमओयू किया गया है।

भारत और उज्बेकिस्तान ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता किया। उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए एमओयू हुआ है। भारत ने अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए 10 लाख डॉलर देने की घोषणा की है। इसके अलावा हिंदी भाषा के लिए लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति के तहत 100 छात्रवृत्तियां देने और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में आईसीसीआर संस्कृत चेयर स्थापित करने की घोषणा की गई है।

भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र यूपीआई को भी उज्बेकिस्तान में विस्तार मिलने जा रहा है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और उज्बेकिस्तान के नेशनल इंटरबैंक प्रोसेसिंग सेंटर (NIPC) के बीच वाणिज्यिक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत के UPI ऐप से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय QR कोड UZQR को स्कैन कर व्यापारिक भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा गुजरात और उज्बेकिस्तान के समरकंद क्षेत्र के बीच साझेदारी संबंध स्थापित करने के लिए भी सहयोग समझौता हुआ है। भारत-उज्बेकिस्तान संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदले।

अरल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए भारत देगा 10 लाख डॉलर।

हिंदी भाषा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्तियां।

ताशकंद में संस्कृत चेयर स्थापित होगी।

उज्बेकिस्तान में UPI ऐप से UZQR स्कैन कर भुगतान की सुविधा।

बौद्ध स्थलों फयाज टीपा और करा टीपा के संरक्षण में भारत सहयोग करेगा।

भूविज्ञान, खनिज, आयुर्वेद, पर्यटन, पर्यावरण, उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध में सहयोग बढ़ेगा।

उज्बेकिस्तान में चीनी J-10CE लड़ाकू विमान, क्या मध्य एशिया में टूट गया रूस का दबदबा ? पुतिन को झटका

एजेंसी बिश्केक

चीन ने मध्य एशिया में रूस के दबदबे को तोड़ते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। उसने पूर्व सोवियत देश उज्बेकिस्तान को J-10CE लड़ाकू विमान बेचा है। ये लड़ाकू विमान उज्बेकिस्तान के कार्शी-खानाबाद एयर बेस पर दिखाई दिए हैं। इनकी संख्या 6 बताई गई है। इससे पहले तक उज्बेकिस्तान सैन्य हथियारों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर था। 28 अगस्त 2026 को उज्बेकिस्तान के पैंतीसवें स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियों के दौरान ब्रॉडकास्ट किए गए इस फुटेज में J-10CE लड़ाकू विमान को काश्कादार्या में स्ट्रेटेजिक K2 फैसिलिटी में उड़ते और लैंड करते हुए दिखाया गया।

चीन और उज्बेकिस्तान ने J-10CE लड़ाकू विमानों के लिए कथित तौर पर 1 बिलियन डॉलर का समझौता किया है। इस समझौते में उज्बेकिस्तान को 24 J-10CE लड़ाकू विमान, हथियार, ट्रेनिंग और सपोर्ट कवर मिलने वाला है। इस खरीद से उज्बेकिस्तान की बियॉन्ड-विजुअल-रेंज कैपेबिलिटी में भारी इजाफा होगा। इसके साथ ही खराब होते पूर्व सोवियत युग के फ्लीट और अनिश्चित रूसी सहायता पर भी निर्भरता घटेगी।

उज्बेकिस्तान या चीन ने इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। दोनों देशों ने इस समझौते को गुप्त रखा है। इसके बावजूद एक ऑपरेशनल एयरबेस पर एक साथ छह J-10CE लड़ाकू विमान का दिखना इस बात का पक्का सबूत है कि यह समझौता अब अडवांस फेज में है। इसके लिए उज्बेकिस्तान के पायलटों की चीन में ट्रेनिंग में पूरी हो चुकी है। मेंटीनेंस स्टाफ भी प्रशिक्षित हैं और जरूरी ग्राउंड इक्विपमेंट्स, ऑपरेटिंग फैसिलिटी का निर्माण किया जा चुका है।

J-10CE का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे रडार, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और PL-15E मिसाइल उज्बेकिस्तान की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। यह लड़ाकू विमान उज्बेकिस्तान के पुराने MiG-29 की जगह लेगा, जो आज के समय के हिसाब से काफी पुराने हो चुके हैं। इससे चीन और उज्बेकिस्तान में रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य एशिया में चीनी हथियारों की मांग बढ़ने की भी उम्मीद है।

मोदी-मिर्जियोयेव की मुलाकात में हुए बड़े ऐलान! 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य, AI से लेकर रक्षा और अंतरिक्ष तक साथ आएंगे भारत और उज्बेकिस्तान

एजेंसी नुक

उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। इस दौरान भारत और उज्बेकिस्तान ने अपने रिश्तों को 'Comprehensive Strategic Partnership' यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह उनकी उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा है। उन्होंने राष्ट्रपति मिर्जियोयेव और उज्बेकिस्तान की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए आभार जताया।

पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ उन्हें करीब एक दशक से काम करने का मौका मिला है और इस दौरान दोनों की 10 से ज्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं। उन्होंने मिर्जियोयेव की सकारात्मक सोच, दूरदर्शी नजरिए और लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा की तारीफ की। पीएम मोदी ने भारत के प्रति उनकी दोस्ती और प्रतिबद्धता के लिए भी आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। अब दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भी कहा कि मौजूदा 1 अरब डॉलर का व्यापार दोनों देशों की क्षमता की सीमा नहीं है। उन्होंने पहले 5 अरब डॉलर और आगे चलकर 10 अरब डॉलर के व्यापार तक पहुंचने का भरोसा जताया। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भारत की डिजिटल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप क्षेत्र में प्रगति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान इन क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों के साथ अपने सहयोग को जोड़ना चाहता है। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति और रोडमैप तैयार करने पर भी सहमति जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों में युवा, इनोवेशन, समावेशी विकास और आधुनिक तकनीक को खास महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये चीजें 'यंग उज्बेकिस्तान' और 'विकसित भारत 2047' दोनों की सोच के केंद्र में हैं।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने बताया कि दोनों देशों ने कई नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इनमें ऊर्जा, संस्कृति, महत्वपूर्ण खनिज , मांस्युटिकल्स, ज्वेलरी और कृषि शामिल हैं। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रोडमैप तैयार करने का फैसला किया है। इसके लिए भारत और उज्बेकिस्तान की टीमें एक-दूसरे के देशों का दौरा करेंगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में सहयोग को भी लोगों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी पर भी साथ पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से और मजबूत होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी दोनों देश एक-दूसरे के लिए फायदेमंद सहयोग बढ़ाएंगे। कृषि और पारंपरिक चिकित्सा में बढ़ेगा सहयोग पीएम मोदी ने कहा कि कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान की क्षमताएं एक-दूसरे की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान के हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के अनुभव और भारत की आधुनिक कृषि तकनीकों को साथ लाकर दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। वहीं, उज्बेकिस्तान की औषधीय जड़ी-बूटियों और भारत की आयुर्वेद विशेषज्ञता को एक अच्छा मेल बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े आज के समझौते दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत-उज्बेकिस्तान की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से दोनों देशों के शहरों और राज्यों के बीच साझेदारी स्थापित की जाएगी। इसके तहत शहरी प्रबंधन, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने बताया कि दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही बढ़ाने के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री व्यवस्था अपनाई गई है। इसके साथ ही सीधी उड़ानों को बढ़ावा देने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ज्यादा लोग यात्रा कर सकेंगे और दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क और मजबूत होंगे।

गंगा जल बंटवारा संधि को रिन्यू करने के लिए बेचैन क्यों है बांग्लादेश ? एक्सपर्ट ने कारण गिना दिए

एजेंसी ढाका

बांग्लादेश गंगा जल बंटवार संधि के नवीनीकरण के लिए परेशान है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह संधि 12 दिसंबर 1996 को 30 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि कि मियाद इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाली है। ऐसे में इस संधि को रिन्यू करने की आवश्यकता है, लेकिन बांग्लादेश अब इसमें नई शर्तों को शामिल करना चाहता है। बांग्लादेश के कई विशेषज्ञ भी तारिक रहमान सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें संधि को रिन्यू करते समय इसकी शर्तों पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में हालात काफी बदल गए हैं। बांग्लादेश के मीडिया डेली स्टार से बात करते हुए एशियन ग्रोथ रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर और संयुक्त राष्ट्र में विकास अनुसंधान के पूर्व प्रमुख एस नजरुल इस्लाम ने कहा कि इस संधि को रिन्यू करने की पहल बांग्लादेश की तरफ से पहले से करनी चाहिए, क्योंकि इसकी असली जरूरत हमें हैं। उन्होंने आशंका जताई कि संधि के खत्म होने पर भारत अपनी ऊपरी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर सहायक नहर की 40,000 क्यूसेक क्षमता सीमा के अधीन रहते हुए, गंगा के जितना चाहे उतना जल मोड़ सकता है। बांग्लादेश के हित में यह स्थिति नहीं है।उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश को गंगा जल बंटवारा संधि को रिन्यू करने के लिए प्रमुख रूप से तीन काम करने चाहिए। पहला- संधि के संबंध में बांग्लादेश का रुख स्पष्ट करना; दूसरा- यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना कि उसका रुख स्वीकार किया जाए; और तीसरा- वार्ता के लिए एक सक्षम टीम का गठन करना। उन्होंने तारिक रहमान सरकार से अनुरोध किया कि इसके लिए तैयारियों को तुरंत शुरू करना होगा, क्योंकि अब संधि के खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा है और बांग्लादेश के हित को साधने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी होगी।एस नजरुल इस्लाम ने आगे कहा, अब तक, भारत और बांग्लादेश के बीच नदी बंटवारे की वार्ता नदियों के "व्यावसायिक दृष्टिकोण" के आधार पर की गई है। इस दृष्टिकोण के तहत, नदियों को मुख्य रूप से वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में देखा जाता है, जिनका पानी समुद्र तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि बांग्लादेश को इसके विपरीत "पारिस्थितिक दृष्टिकोण" को भी शामिल करना चाहिए, जो नदियों के आर्थिक महत्व को नजरअंदाज किए बिना उनके पारिस्थितिक कार्यों पर जोर देता है।उन्होंने दावा किया कि अगर बांग्लादेश वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर नदी जल बंटवारे की वार्ता में शामिल होता है, तो उसकी हार निश्चित है क्योंकि भारत नदी के जल की सैकड़ों वाणिज्यिक आवश्यकताएं प्रस्तुत कर देगा, जिससे बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल का पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर अपनाए गए रुख का जिक्र किया और कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल को सिंचाई के लिए अधिक जल की आवश्यकता है, वैसे ही बांग्लादेश के लिए भी है। उन्होंने तारिक रहमान सरकार से भारत के सामने अपनी मांग को जोरदार तरीके से रखने की मांग भी की।

पीएम मोदी की कल पुतिन से मुलाकात, 50 मिनट की बैठक तय, किन मुद्दों पर होगी बात

एजेंसी बिश्केक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। करीब 50 मिनट निर्धारित इस बैठक में भारत-रूस संबंधों के साथ-साथ कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मोदी-पुतिन की बातचीत में ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दा हो सकता है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने नई दिल्ली में प्रस्तावित BRICS शिखर सम्मेलन में भी दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल और उर्वरक का बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। ऐसे में दोनों नेता तेल और गैस की आपूर्ति, उर्वरकों की उपलब्धता और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा कर सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार में जारी अस्थिरता के बीच भारत के लिए रूसी ऊर्जा आपूर्ति अहम है।

रक्षा सहयोग भी बैठक के एजेंडे में रह सकता है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा साझेदारी है। सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहयोग और रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन को आगे बढ़ाने पर चर्चा संभव है। भारत-रूस व्यापार भी अहम विषय रहेगा।

दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है, लेकिन व्यापार में असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय है। बैठक में भारतीय उत्पादों के रूस में निर्यात, निवेश, भुगतान व्यवस्था और व्यापार को अधिक संतुलित बनाने के उपायों पर चर्चा हो सकती है।

अरब देशों पर खतरे की घंटी, जलवायु परिवर्तन से खड़ा हो सकता है भोजन-पानी का संकट

एजेंसी रियाद

जलवायु परिवर्तन अरब दुनिया में एक बड़े खतरे की घंटी बजा रहा है। पूरे अरब जगत में पानी की कमी, खराब होती फसलें और खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ दिख रहा है। इस इलाके में पहले से ही पानी की भारी कमी है। अब जलवायु परिवर्तन की वजह से भुखमरी और मानवीय संकट के प्रति और बहुत ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। इस स्थिति को लेकर एक्सपर्ट ने चेताया है। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के कोऑर्डिनेटर अहमद मुख्तार ने अरब न्यूज को बताया है कि प्रति व्यक्ति ताजे पानी की उपलब्धता के मामले में अरब दुनिया का सबसे ज्यादा पानी की कमी वाला इलाका है। यहां खेती के लायक जमीन 5 प्रतिशत से कम है और रेगिस्तान का दायरा तेजी से बढ़ रहा है।

अरब इलाके में FAO स्थानीय सरकारों और समुदायों के साथ मिलकर पानी के टिकाऊ प्रबंधन के तरीके लागू करता है। साथ ही यह खेती की पैदावार बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन से खाने-पीने की चीजों की कमी के संकट से कमजोर आबादी को बचाने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाता है। स्थानीय स्तर पर ताजे पानी का ज्यादातर इस्तेमाल खेती में ही होता है इसलिए पानी की कमी से किसान समुदाय बहुत तेजी से मुश्किल में पड़ जाते हैं। उन्हें खाने-पीने की चीजों के लिए अस्थिर ग्लोबल इंपोर्ट मार्केट पर निर्भर रहना पड़ता है, जो टिकाऊ नहीं है। अहमद मुख्तार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन इस समस्या को और बढ़ा रहा है। जलवायु परिवर्तन सरकारों के इरादों और मौजूदा आर्थिक संसाधनों पर तेजी से असर डाल रहा है। इस इलाके में कई बड़े देश तकनीकी रूप से औद्योगीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कार्बन फुटप्रिंट शायद बढ़ेंगे। आयात पर बढ़ेगी निर्भरता

अरब देश खाने-पीने की चीजों के आयात पर बहुत निर्भर है। FAO का अनुमान है कि 2031 तक इस इलाके में खाने-पीने की चीजों की कुल खपत का दो-तिहाई हिस्सा इंपोर्ट से आएगा। कुछ खाड़ी देश तो अपनी खाने-पीने की जरूरतों का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा इंपोर्ट से ही पूरा करते हैं। अरब की समस्या यह है कि पानी की कमी के बावजूद देश खेती में आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ें। मुख्तार ने कहा कि इस समस्या को आर्थिक नजरिए से देखने की जरूरत है। इसका कोई एक समाधान नहीं है। आत्मनिर्भरता का विचार आदर्श लगता है लेकिन असल में कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। जलवायु से जुड़े झटके खाने-पीने की चीजें बड़े पैमाने पर पैदा करने वाले देशों को प्रभावित करते हैं। ये सप्लाई कम कर सकते हैं, कीमतें बढ़ा सकते हैं और व्यापार में रुकावट डाल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के क्षेत्रीय निदेशक समर अब्देलजाबेर ने अरब न्यूज को बताया कि जलवायु से जुड़े झटके फसल की पैदावार कम कर रहे हैं, लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इससे कमजोर परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन पाना मुश्किल हो रहा है। संघर्ष वाले इलाकों में ये असर ज्यादा है। अब्देलजाबेर ने कहा, 'जलवायु परिवर्तन एक ऐसे खतरे के तौर पर काम करता है, जो दूसरे खतरों को बढ़ा देता है। इससे खाद्य प्रणालियों और जरूरी सेवाओं पर दबाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से फसलों की पैदावार कम होगी तो फल, सब्जियां और पशुपालन को जोखिम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे पानी के सीमित स्रोतों और स्थिर जलवायु परिस्थिति पर निर्भर हैं।'

महिला टी20 एशिया कप में भारत की शानदार शुरुआत, थाईलैंड को 94 रन से हराया

एजेंसी नई दिल्ली

भारत ने सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा (64 रन) के आक्रामक अर्धशतक के बाद बाएं हाथ की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा (सात गेंद में बिना रन दिए तीन विकेट) के रिकॉर्ड स्पेल और मध्यम गति की गेंदबाज नंदनी शर्मा (18 रन देकर तीन विकेट) के शानदार प्रदर्शन से रविवार को यहां महिला टी20 एशिया कप ग्रुप ए मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद भारत ने शेफाली के 19वें टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक (26 गेंद में छह चौके और तीन छक्के) से नौ विकेट पर 159 रन का स्कोर खड़ा किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने थाईलैंड की टीम 16.1 ओवर में महज 65 रन पर सिमट गई।

थाईलैंड के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज नानापत कोंचारोएंकई (41 रन) एकमात्र खिलाड़ी रहीं जो दोहरे अंक तक पहुंची। अपना 150वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहीं दीप्ति (यह उपलब्धि हासिल करने वाली हरमनप्रीत और मंधाना के बाद केवल तीसरी भारतीय खिलाड़ी) ने रिकॉर्ड स्पेल में सात गेंद में एक मेडन से बिना कोई रन दिए तीन विकेट झटके। नंदनी शर्मा ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि श्री चरणी ने तीन ओवर में 10 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए।

क्रांति गौड़ ने चार ओवर में 26 रन देकर थाईलैंड की पारी का पहला विकेट झटका। इससे पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद थाईलैंड की स्पिनरों ने सुलीपोर्ण लाओमी की अगुआई में भारत को बड़े स्कोर से वंचित कर दिया। शेफाली अपनी 36 गेंद की पारी में आठ चौके और तीन छक्के लगाए जिससे भारतीय टीम 200 से अधिक के स्कोर तक पहुंचने की स्थिति में दिख रहा था।लेकिन इसके बाद पारी बिखर गई। भारत के लिए पदार्पण करने वाली प्रतिका रावल ने 22 रन और स्मृति मंधाना ने 19 रन का योगदान दिया। भारत ने 21 रन के अंदर चार विकेट गंवा दिए।

लाओमी की गेंदों में बदलाव, ड्रिफ्ट और फ्लाइट ने भारतीय मध्यक्रम को परेशानी में डाल दिया। 28 वर्षीय लेग स्पिनर लाओमी ने 26 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने शेफाली और ऋचा घोष को लगातार दो गेंद पर आउट किया। ऑफ स्पिनर सुनीदा चातुरोंगरत्ताना ने 31 रन देकर दो विकेट हासिल किए। मंधाना ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने फनिता माया के पहले ओवर में तीन चौकों की मदद से 13 रन बटोरे। मंधाना 10 गेंदों में 19 रन बना चुकी थीं, तभी सुवानचोनरथी के शानदार सीधे थ्रो ने उन्हें दूसरे रन के प्रयास में रन आउट कर दिया। हालांकि, शेफाली का दबदबा जारी रहा। उन्होंने बाएं हाथ की स्पिनर और कार्यवाहक कप्तान थिपाट्चा पुथावोंग के खिलाफ लगातार चौके लगाए। इसके बाद वह क्रीज से आगे बढ़ीं और सुनीदा की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा। फिर शेफाली ने लाओमी पर लांग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे 10 ओवर के बाद भारत दो विकेट पर 100 रन के स्कोर पर आसानी से आगे बढ़ रहा था, तभी लाओमी ने पदार्पण कर रही प्रतिका रावल को आउट कर दिया जो 18 गेंद खेलने के बाद बोल्ड हो गईं।

श्रीलंका से छीनी गई 2027 विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, ICC का बड़ा फैसला

एजेंसी नई दिल्ली

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और श्रीलंका क्रिकेट के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा एक बार फिर देश के क्रिकेट को भुगतना पड़ा है। श्रीलंका से साल 2027 में आयोजित होने वाली पहली आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली गई है। 14 से 28 फरवरी तक खेले जाने वाले इस 6-टीमों के टूर्नामेंट के लिए नए मेजबान देश का फैसला आईसीसी की आगामी बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। श्रीलंका क्रिकेट में लगातार बढ़ रहे सरकारी हस्तक्षेप के कारण आईसीसी ने यह कड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में श्रीलंका क्रिकेट का संचालन सरकार द्वारा गठित ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कर रही है। आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य बोर्ड का संचालन स्वतंत्र होना चाहिए और उसमें राजनीतिक या सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी के सचिव प्रकाश शेफ्टर ने इस खबर की पुष्टि की और कहा, 'हां, इस टूर्नामेंट को श्रीलंका से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है। यह किसी अन्य स्थान पर खेला जाएगा, लेकिन फिलहाल यह तय नहीं है कि नया मेजबान कौन होगा।' न

यह पहला मौका नहीं है जब श्रीलंका से किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी छीनी गई हो, साल 2023 में सरकारी हस्तक्षेप के चलते आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद 2024 अंडर-19 पुरुष विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका से छीनकर दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी गई थी। इस फैसले का असर श्रीलंका टीम की टूर्नामेंट में भागीदारी पर भी पड़ सकता है। मूल नियमों के अनुसार मेजबान देश होने के नाते श्रीलंका को 6 टीमों के इस टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश मिलना था (श्रीलंका वर्तमान में आईसीसी रैंकिंग में छठे स्थान पर है)। अब यदि मेजबानी किसी ऐसी टीम को मिलती है जो रैंकिंग में नीचे है, तो श्रीलंका के क्वालिफिकेशन पर संकट खड़ा हो सकता है। हालांकि, आईसीसी ने अभी तक संशोधित क्वालिफिकेशन प्रक्रिया का ऐलान नहीं किया है।

लॉर्ड्स में मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, 5 विकेट लेकर वकार यूनिस के बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, बने ऐसा करने वाले 7वें पाकिस्तानी

एजेंसी लंदन

लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने अपनी धारदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। अब्बास ने पहली पारी में 4 विकेट चटकाने के बाद दूसरी पारी में भी 5 विकेट हॉल (5/57) पूरा किया। उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी के 52वें ओवर की पहली गेंद पर ओली रॉबिन्सन को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराकर अपना पंजा खोला। इस घातक गेंदबाजी के साथ ही मोहम्मद अब्बास ने टेस्ट क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स मैदान पर कई बड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। अब्बास लॉर्ड्स में एक टेस्ट पारी में 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के सातवें गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले खान मोहम्मद, मुदस्सर नजर, वकार यूनिस, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद आमिर और यासिर शाह यह कारनामा कर चुके हैं। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के लिए सर्वश्रेष्ठ पारी गेंदबाजी आंकड़ा मुदस्सर नजर के नाम है। उन्होंने साल 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 32 रन देकर 6 विकेट झटके थे। मैच में 9 विकेट (9/130) हासिल करते ही मोहम्मद अब्बास ने लॉर्ड्स में एक टेस्ट मैच में किसी पाकिस्तानी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने का वकार यूनिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वकार ने जुलाई 1996 में लॉर्ड्स टेस्ट में 154 रन देकर 8 विकेट लिए थे। लॉर्ड्स टेस्ट मैच में पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े यासिर शाहः 60.0 ओवर, 141 रन, 10 विकेट (जुलाई 2016) मोहम्मद अब्बासः 42 ओवर, 130 रन, 9 विकेट (अगस्त 2026) मोहम्मद अब्बासः 31.0 ओवर, 64 रन, 8 विकेट (मई 2018) वकार यूनिसः 49.0 ओवर, 154 रन, 8 विकेट (जुलाई 1996) लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पाकिस्तानी गेंदबाज बने अब्बास ओली रॉबिन्सन का विकेट लेते ही अब्बास ने लॉर्ड्स मैदान पर कुल 17 विकेट पूरे कर लिए। इसके साथ ही उन्होंने लॉर्ड्स में पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वकार यूनिस (17 विकेट) की बराबरी कर ली है। खास बात यह है कि अब्बास ने यह मुकाम महज 2 टेस्ट मैचों (4 पारियों) में हासिल किया, जबकि वकार ने 3 टेस्ट मैच खेले थे। मोहम्मद अब्बास (2018-2026): 2 मैच, 17 विकेट, बेस्टः 5/57

वकार यूनिस (1992-2001): 3 मैच, 17 विकेट, बेस्टः 5/91 मोहम्मद आमिर (2010-2018): 3 मैच, 14 विकेट, बेस्टः 6/84 वसीम अकरम (1987-2001): 4 मैच, 12 विकेट, बेस्टः 4/66

वैभव सूर्यवंशी की टीम के आगे रिंकू सिंह का चला बल्ला, ईस्ट जोन के खिलाफ ढहती सेंट्रल जोन की पारी को ऐसे उबारा

एजेंसी बेंगलुरु

दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन के बीच खेले जा रहे मुकाबले में रिंकू सिंह ने एक बार फिर संकटमोचक की भूमिका निभाई है। ईस्ट जोन के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही ठहराते हुए सेंट्रल जोन के ऊपरी क्रम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि, जब टीम गहरी मुसीबत में नजर आ रही थी, तब रिंकू सिंह ने मैदान पर मोर्चा संभाला और आक्रामक अर्धशतकीय पारी खेलकर सेंट्रल जोन की मैच में वापसी कराई।

ईस्ट जोन के तेज गेंदबाजों मुकेश कुमार, अभिजीत सरकार और मोहम्मद शमी की धारदार गेंदबाजी के आगे सेंट्रल जोन के बल्लेबाज काफी दिक्कत में दिखे। अमन मोखाड़े (8), कुणाल चंदेला (6), कप्तान रजत पाटीदार (12) और फॉर्म में चल रहे आर्यन जुयाल (46) के आउट होने से सेंट्रल जोन ने महज 125 रन तक अपने 5 अहम विकेट गंवा दिए थे।

एक छोर से लगातार गिरते विकेटों के बीच रिंकू सिंह ने न केवल विकेट पतन को रोका बल्कि रन गति को भी बनाए रखा। रिंकू ने 88 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 60 रनों की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 68.18 का रहा। रिंकू ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर पारी को संभाला। रिंकू ने हर्ष दुबे के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 85 गेंदों में 55 रन जोड़े और टीम का स्कोर 180 के पार पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने सारांश जैन के साथ 7वें विकेट के लिए 29 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया।

रिंकू सिंह की इस जुझारू पारी के बदौलत सेंट्रल जोन ने 70 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। हालांकि मुकेश कुमार की गेंद पर अनुकूल रॉय को कैच थमाकर रिंकू 213 के स्कोर पर 8वें विकेट के रूप में आउट हो गए, लेकिन तब तक वे टीम को एक लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा चुके थे। ईस्ट जोन के लिए मुकेश कुमार ने 3, अभिजीत सरकार और मोहम्मद कौनैन कुरैशी ने 2-2 विकेट जबकि मोहम्मद शमी ने 1 विकेट चटकाया है।

व्यापार

मोदी का टारगेट रहेगा अधूरा! भारत की 7% ग्रोथ भी उसे नहीं बना पाएगी विकसित

एजेंसी नई दिल्ली

पिछली तिमाही में भारत की विकास दर 7% से ज्यादा रहने का अनुमान है। यह दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चौंकाने वाली हो सकती है। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित राष्ट्र' के सपने को पूरा करने के लिए यह रफ्तार शायद काफी नहीं है। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत 2047 तक 'विकसित' का दर्जा हासिल कर ले। यह ब्रिटिश शासन से आजादी के 100 साल पूरे होने का साल होगा। देश के सबसे बड़े सरकारी थिंक-टैंक के सीनियर अधिकारी अशोक लाहिड़ी के अनुसार, दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को इस टारगेट तक पहुंचने के लिए 21 सालों तक हर साल 9.25% की दर से बढ़ना होगा। 'विकसित भारत' का यह टारगेट पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का मुख्य एजेंडा बन गया है। हालांकि, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मौजूदा विकास दर को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था उनके विजन से पीछे रह जाएगी। 2000 और 2024 के बीच विकास दर औसतन 6.3% रही। यह 7.5%-8% की मौजूदा संभावित दर से काफी कम है। पिछले 50 सालों में अर्थव्यवस्था सिर्फ तीन बार यानी 1975, 1988 और 2021 में 9.25% या उससे ज्यादा की दर से बढ़ी है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की लंदन स्थित अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने कहा कि इस टारगेट को हासिल करने के लिए विकास दर में बहुत ज्यादा और लगातार तेजी की जरूरत होगी। यह अर्थव्यवस्था के बढ़ने और आधार (बेस) के बड़ा होने के साथ और मुश्किल होता जाएगा। सोमवार को आने वाले डेटा से पता चल सकता है कि पिछली तिमाही में अर्थव्यवस्था एक साल पहले की तुलना में 7.3% बढ़ी। यह पिछली तीन तिमाहियों में रही 7.8% की दर से कम है। 8% से कम विकास दर भारत को 'मिडिल-इनकम ट्रैप' में फंसा सकती है, जहां अमीर अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला करने के लिए उत्पादकता और कौशल में काफी सुधार होने से पहले ही बढ़ती मजदूरी देश के कम लागत वाले फायदे को खत्म कर देती है। 'हाई-इनकम' वाले देश का दर्जा पाने का सफर बहुत लंबा है। नीति आयोग के लाहिड़ी के अनुसार, 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,813 थी। इस स्तर को पार करने के लिए 2047 तक इसे छह गुना से ज्यादा बढ़कर लगभग $18,000 तक पहुंचना होगा। ओवरसीज-चाइनीज बैंकिंग कॉर्प की इकोनॉमिस्ट लावण्या वेंकटेश्वरन का कहना है कि भारत की इकॉनमी में काफी कमजोरियां हैं। उन्होंने देश के करंट-अकाउंट और बजट घाटे के साथ बाहरी बैलेंस को फंड करने के लिए अस्थिर कैपिटल इनफ्लो पर निर्भरता को जोखिम बताया। यही एक वजह है कि विदेशी निवेशकों के बीच देश का आकर्षण कम हो रहा है, और इस साल अब तक भारतीय रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही है। बैंक ऑफ़ अमेरिका कॉर्प के फ़ंड मैनेजरों के अगस्त के सर्वे में, भारत ने एशिया के सबसे कम पसंद किए जाने वाले स्टॉक मार्केट के तौर पर इंडोनेशिया की जगह ले ली। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि एक समाधान मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। यह मोदी सरकार के एजेंडे में भी है। हालांकि, एक दशक से ज्यादा समय से भारत की जीडीपी में इस सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग 16%-17% पर ही अटकी हुई है। इसकी तुलना पीएम मोदी के 25% के टारगेट से की जा सकती है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि हाई-टेक एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना और इंपोर्टेड एनर्जी पर निर्भरता कम करना इकॉनमिक मोमेंटम को तेज करने के अन्य तरीके हैं।

खाद किल्लत की अटकलों के बीच सरकार ने सख्त की ट्रैकिंग, ऐसे रखा जाएगा हिसाब

एजेंसी नई दिल्ली

देश कई हिस्सों में खाद की किल्लत की अटकलों के बीच सरकार एक्शन में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र सरकार एक देशव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करने में जुटी है। यह प्लेटफॉर्म फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से लेकर रिटेल बिक्री तक ट्रैकिंग करता है। इसमें किसानों के जमीन के रिकॉर्ड के साथ खरीद को जोड़ने और सब्सिडी पेमेंट की बारीकी से निगरानी करने के लिए नए टूल जोड़े जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम ' (iFMS) पहले से ही 14 करोड़ से ज्यादा आधार-लिंक्ड खरीदारों और 2,50,000 से अधिक रिटेलर्स को इससे ट्रैक करता है। हर साल यह लगभग 7 करोड़ टन फर्टिलाइजर की बिक्री का हिसाब-किताब रखता है। यह सिस्टम सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी का आधार है। iFMS को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की तकनीकी मदद से फर्टिलाइजर विभाग चलाता है। नए डैशबोर्ड डेवलप कर रहा विभाग एक सरकारी बयान के अनुसार, विभाग नए डैशबोर्ड विकसित कर रहा है। ये अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और रिटेलर स्तर पर प्रोडक्शन, इंपोर्ट, डिस्पैच, स्टॉक और रिटेल बिक्री की पूरी जानकारी देंगे। इसका मकसद असामान्य ट्रेंड या सप्लाई में कमी का पहले ही पता लगाना है। विभाग ने iFMS को किसान, जमीन और फसल डेटाबेस के साथ जोड़ने का काम भी किया है। हरियाणा के 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' प्रोग्राम के साथ एक पायलट इंटीग्रेशन और उसके बाद केंद्र सरकार की 'एग्रीस्टैक' पहल से जुड़ने की कोशिशों के तहत फर्टिलाइजर खरीदारों को जमीन के रिकॉर्ड से मिलाने के तरीकों का परीक्षण किया गया। इस काम से मौजूदा जमीन और फसल डेटा की कमियों का पता चला।

उस काम को आगे बढ़ाते हुए विभाग ने फर्टिलाइजर बिक्री के लिए एक फ्रेमवर्क शुरू किया है। यह मोबाइल बुकिंग ऐप को मौजूदा पॉइंट-ऑफ-सेल नेटवर्क से जोड़ता है। इस फ्रेमवर्क के तहत किसान अपनी जमीन और मालिकाना हक की जानकारी वेरिफाई होने के बाद एग्रीस्टैक-आधारित ID का इस्तेमाल करके फर्टिलाइजर बुक करते हैं। इससे एक QR कोड बनता है। इसे रिटेलर स्कैन करके मांगी गई और खरीदी गई मात्रा की तुलना करते हैं। इस फ्रेमवर्क को चरणों में लागू किया जा रहा है। इसमें विभाग और शामिल राज्य बड़े पैमाने पर इसे लागू करने से पहले बुकिंग के व्यवहार और खपत के पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस डेटा से प्रति हेक्टेयर, जमीन के आकार, फसल और प्रोडक्ट के हिसाब से फर्टिलाइजर के इस्तेमाल का विश्लेषण किया जा सकेगा। साथ ही, किसान की जरूरत और उनकी खरीद के बीच के अंतर का भी पता चल सकेगा।विभाग ने 'व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम' भी शुरू किया है जो डिस्पैच रिकॉर्ड को रियल-टाइम व्हीकल लोकेशन डेटा से जोड़ता है। इससे अधिकारी रास्ते में शिपमेंट की निगरानी कर सकते हैं। देरी का पता लगा सकते हैं। यह सिस्टम रास्ते में सामान और स्टॉक के स्तर को ट्रैक करने वाले मौजूदा टूल के अलावा काम करता है।

रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक, फिर भारत से अभी मंगा रहा पेट्रोल

एजेंसी नई दिल्ली

रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। वह अपने देश में पेट्रोल की राशनिंग कर रहा है। कारण है कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने उसकी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। ईंधन की सप्लाई में रुकावट डाली है। देश रिकॉर्ड स्तर के करीब कच्चा तेल निकालना जारी रखे हुए है। जबकि उसकी अपनी राजधानी में ही पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी हो रही है। यह विरोधाभास रूस के कच्चे तेल के उत्पादन और उस कच्चे तेल को इस्तेमाल के लायक ईंधन में बदलने की उसकी क्षमता के बीच के अंतर की ओर ध्यान खींचता है। TOI की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मॉस्को में पेट्रोल स्टेशनों ने ईंधन की बिक्री पर फिर से सीमाएं लागू कर दी हैं। कारण है कि कमी फिर से शुरू हो गई है। गैजप्रोम नेफ्ट ने ऑटोमेटेड स्टेशनों पर पेट्रोल की खरीद को 40 लीटर और अन्य स्टेशनों पर 60 लीटर तक सीमित कर दिया है। जबकि रोजनेफ्ट ने पूरे रूस में प्रति वाहन बिक्री को 30 लीटर तक सीमित किया है। टैटनेफ्ट ने भी 50 लीटर की सीमा तय की है। मॉस्को और आसपास के इलाकों में पेट्रोल स्टेशनों पर लंबी कतारें फिर से लग गई हैं। ये प्रतिबंध जुलाई में कुछ समय के लिए कमी की पिछली लहर के कम होने के बाद लगाए गए हैं। लेकिन, रिफाइनरियों पर नए यूक्रेनी हमलों, साथ ही मौसम के हिसाब से ज्यादा मांग और रिफाइनरी के रखरखाव के कारण सप्लाई फिर से तंग हो गई है। जब रूस के तेल उद्योग को ध्यान में रखा जाता है तो समस्या का दायरा और साफ हो जाता है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के अनुसार, रूस ने 2025 में प्रति दिन लगभग 98.9 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया। इससे वह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश बन गया। नवीनतम IEA डेटा से पता चलता है कि रूस जुलाई 2026 में भी प्रति दिन 87.6 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कर रहा था। यह आंकड़ा जून में दर्ज 88.6 लाख बैरल प्रति दिन से कम था। लेकिन, यह दिखाता है कि रूस भारी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन जारी रखे हुए है। फिर भले ही उसके पेट्रोल बाजार में कमी का सामना करना पड़ रहा हो।

आखिर सुदामा के श्राप से क्यों धरा पर अवतरित हुईं बरसाना की महारानी

राधा रानी को प्रेम की देवी कहा जाता है। भगवान श्रीकृष्ण के जीवन की धारा, राधा जी हैं। माना जाता है कि गोलोक में एक बार श्रीकृष्ण रास करने की इच्छा में लीन थे। तब भगवान श्रीकृष्ण के बाएं भाग से दिव्य स्वरूपा श्रीराधा प्रकट हुई थीं। भगवान श्रीकृष्ण ने धरा पर अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। लेकिन माना जाता है कि बिना श्रीराधा के वासुदेव कृष्ण के ध्येय को दिशा नहीं मिल सकती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीराधा रानी एक श्राप की वजह से श्रीकृष्ण से पहले धरती पर जन्मी थीं।

पतिव्रता नारी थीं श्रीराधा राधा रानी के बिना श्रीकृष्ण की आराधना अधूरी मानी जाती है। भले ही राधा और कृष्ण ने संग में अधिक समय नहीं बिताया हो। लेकिन दोनों एक-दूसरे के दिल में हमेशा बसे रहे। राधा रानी एक पतिव्रता नारी थीं वह अपने पति आयन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहीं। हालांकि श्रीकृष्ण के प्रति राधा रानी का प्रेम सात्विक और निश्छल था।

बरसाना की महारानी बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि रही है। स्कंद पुराण के मुताबिक राधा और कृष्ण की आत्मा एक है। इसी कारण उनको 'राधारमण' कहकर पुकारते हैं। पद्म पुराण में 'परमानंद' रस को श्रीराधा-कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। राधा-कृष्ण की पूजा किए बगैर जीव परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। भविष्य पुराण और गर्ग संहिता के मुताबिक द्वापर युग में श्रीकृष्ण पृथ्वी पर अवतरित हुए थे।

वहीं महाराज वृषभानु की पत्नी कीर्ति के यहां भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवती राधा अवतरित हुई। जिसके बाद भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि राधाष्टमी नाम से प्रसिद्ध हुई। राधा और कृष्ण को पद्म पुराण में 'युगल सरकार' की संज्ञा दी गई है। शिव पुराण में भगवान श्रीकृष्ण के परम मित्र से भिन्न सुदामा गोप द्वारा राधा रानी को श्राप दिए जाने का उल्लेख मिलता है।

धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक गोलोक में निवास करने वाली श्रीराधा को एक श्राप की वजह से पृथ्वी पर आकर श्रीकृष्ण से वियोग सहना पड़ा। श्रीकृष्ण की विरजा नाम की सखी का राधा ने अपमान किया था। अपमान से दुखी होकर विरजा नदी बनकर बहने लगी। तब सुदामा ने क्रोध में आकर श्रीराधा को कड़वे शब्द कहे। जिस पर श्रीराधा ने सुदामा को दानव बनने का श्राप दिया। इसके बाद सुदामा ने भी श्रीराधा को मानव जीवन में जन्म लेने का श्राप दिया।

सावन की शिवभक्ति के बाद भादौ में क्यों गूंजता है भगवान कृष्ण, गणेशजी और ऋषियों का जयघोष

भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जो कर्म, धर्म और जीवन के कर्तव्यों का संदेश देते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का जन्मोत्सव होता है, जो बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इस प्रकार भाद्रपद मास जीवन में कर्म और बुद्धि के समन्वय तथा साधना के माध्यम से सफलता पाने का मार्ग दिखाता है।

भाद्रपद मास चातुर्मास के चार पवित्र महीनों में दूसरा माह है। यह धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टि से संयम, अनुशासन और सादगी अपनाने का समय माना जाता है। इस माह में कुछ लोक व्यवहार और मांगलिक कार्य, जैसे विवाह, सगाई और नए घर का निर्माण वर्जित माने गए हैं। हालांकि, भक्ति, व्रत, स्नान और दान के लिए यह माह विशेष रूप से शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में किए गए पुण्य कार्य जन्म-जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस मास में कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती हैं। जैसे भाद्रपद के दौरान दही का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम में बदलाव के कारण पाचन तंत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। हिन्दू पंचांग में हर तिथि और माह का एक विशेष संदेश छिपा होता है। 'भाद्रपद' शब्द संस्कृत के 'भद्र' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है 'सभ्य'। यह महीना हमें सभ्यता और सौम्यता अपनाने की प्रेरणा देता है। सावन जिस प्रकार रिमझिम वर्षा के रूप में धरती को भिगोता है और उसका पानी गहराई तक उतर जाता है, उसी प्रकार भक्ति भी हमारे अंतर्मन में गहराई तक उतर जानी चाहिए। जब यह भक्ति भीतर तक बस जाती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे व्यक्तित्व में विनम्रता, अपनत्व और समत्व जैसे गुण आ जाते हैं, जो सच्ची सभ्यता का परिचय हैं। भाद्रपद का समय हमें सिखाता है कि जब भी कोई कार्य करें, पूरे समर्पण और उत्साह के साथ करें, साथ ही यह समय की महत्ता भी समझाता है, जैसे तेज बहता पानी जल्दी निकल जाता है, वैसे ही समय भी निरंतर बहता रहता है। इसलिए भाद्रपद मास हमें समय का मूल्य समझने, कार्य में पूर्णता लाने और व्यक्तित्व में सौम्यता बसाने का संदेश देता है।

हेरंब संकष्टी चतुर्थी, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय समय और महत्व

हेरंब चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित एक विशेष तिथि मानी जाती है। इस दिन भक्त भगवान गणेश के हेरंब स्वरूप की पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि, बुद्धि, सौभाग्य तथा परिवार की रक्षा की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हेरंब गणपति भक्तों के भय और संकट को दूर करने वाले, उन्हें अभय प्रदान करने वाले स्वरूप हैं। इसलिए हेरंब चतुर्थी पर गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस साल हेरंब चतुर्थी पर भद्रा का साया है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, तिथि और चंद्रोदय समय

पंचांग के अनुसार, हेरंब संकष्टी चतुर्थी का व्रत सोमवार, 31 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अगस्त को सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर होगी. जबकि, यह तिथि 1 सितंबर को सुबह 8 बजकर 29 मिनट पर समाप्त होगी।

इस दिन पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त मिलेंगे। गणेश जी की पूजा के लिए सुबह 5:58 से 7:34 बजे तक पहला समय रहेगा। इसके बाद 9:10 से 10:46 बजे तक दूसरा मुहूर्त है। शाम को दीप जलाने का समय 6:44 बजे रहेगा।

भद्रा में न करें शुभ काम

हेरंब संकष्टी चतुर्थी पर सुबह 5:58 से 8:50 बजे तक भद्रा रहेगी। इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे समय में मांगलिक और शुभ कार्यों को टालना बेहतर माना जाता है।

संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। 31 अगस्त को चंद्रमा का उदय रात 8:29 बजे होगा। हालांकि, स्थानीय समय के अनुसार, कुछ मिनट का अंतर हो सकता है।

हेरंब चतुर्थी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। हेरंब स्वरूप में गणेश जी को विशेष रूप से संकटों से रक्षा करने वाला माना जाता है। मान्यता है कि हेरंब चतुर्थी के दिन श्रद्धापूर्वक गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और भक्त को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा से हेरंब गणपति की आराधना करने से भगवान गणेश अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और परिवार में सुख-शांति का वास बना रहता है।

आर्थिक राशिफलः कर्क और मकर राशिवालों की आर्थिक स्थिति हगी मजबूत

मेष राशिः खर्चों की देखरेख और दफ्तर में नई पहल पैसों की स्थिति संभली रहेगी। बिना सोचे खरीदारी से बचें। षष्ठ भाव में शुक्रदेव होने से छोटे-छोटे खर्चों की जांच करें, नहीं तो बचत पर असर पड़ सकता है। काम, सेहत या रोज की जरूरतों पर खर्च हो सकता है। बड़ा जोखिम लेने से बचें। दफ्तर में आपका भरोसा मजबूत रहेगा। पंचम भाव में सूर्यदेव और बुधदेव आपको अपने विचार खुलकर रखने में मदद करेंगे। बड़े अधिकारियों के सामने अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मिथुन राशि के मंगलदेव के प्रभाव से एक साथ बहुत सारे काम हाथ में न लें।

वृष राशिः बचत का सही नियोजन और काम में स्थिरता पैसों की प्राथमिकताओं को जांचने के लिए अच्छा दिन है। तृतीय भाव में विराजमान गुरु बृहस्पतिदेव कमाई बढ़ाने की समझ देंगे। सिर्फ सुंदर दिखने पर चीजें न खरीदें। कन्या राशि के शुक्रदेव के प्रभाव से निर्णय लेने में बहुत ज्यादा देरी न करें। काम में धीरज रखना होगा। मिथुन राशि के मंगलदेव से काम की गति तेज रहेगी। नया काम शुरू करने से पहले जरूरी पेंडिंग काम पूरा करें। आपका शांत मन और लगातार मेहनत दूसरों को प्रभावित करेगी। कहीं भी वादा करने से पहले पूरी जांच कर लें।

मिथुन राशिः समझदारी से बचत और काम में तेजी आपकी राशि में मंगलदेव होने से कमाई बढ़ाने की इच्छा तेज रहेगी। नए तरीके खोजने का मन करेगा। जल्दबाजी में फैसले न लें। कन्या राशि के शुक्रदेव की वजह से नियम से बजट बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आज आपकी बात ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आपकी राशि के मंगलदेव तेजी देंगे और सिंह राशि के बुधदेव आत्मविश्वास से बात रखने में मदद करेंगे। बैठकों, बातचीत, लेखन और बिक्री से जुड़े कामों में लाभ होगा। साथियों से कड़वे बोल न बोलें।

कर्क राशिः धन की मजबूती और दफ्तर में निरंतरता आपकी राशि में गुरु बृहस्पतिदेव होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा। मीन राशि में चंद्रदेव होने से कुछ फैसलों से मन का जुड़ाव रहेगा। परिवार से जुड़े पैसों के मामलों में धीरज रखें। काम में लगातार बढ़त दिखेगी। वरिष्ठ अधिकारियों या अनुभवी लोगों से मदद मिल सकती है। मीन राशि में शनिदेव की उल्टी चाल पुराने छूटे कामों पर ध्यान देने को कह रही है। काम की गति थोड़ी धीमी रहे तो भी घबराएं नहीं।

सिंह राशिः समझदारी से खर्च और दफ्तर में पहचान आपकी राशि में सूर्यदेव और बुधदेव होने से पैसों के फैसलों में भरोसा रहेगा। खुद को बेहतर बनाने या पढ़ाई पर खर्च करना सही रहेगा। कन्या राशि के शुक्रदेव सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करने से मना करते हैं। फालतू खर्च रोकें। दफ्तर में आपकी पूछ बढ़ेगी। सूर्यदेव संचालन करने की ताकत देंगे और बुधदेव बात साफ रखने में मदद करेंगे। विचार रखने या बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए दिन अच्छा है। अपने भरोसे को कड़ा न बनने दें, दूसरों की बात भी सुनें।

कन्या राशिः बजट पर ध्यान और काम में निखार आपकी राशि में कमजोर शुक्रदेव होने से ध्यान धन की सुरक्षा पर रहेगा। हर बात पर बहुत ज्यादा न सोचें। अपने बजट को देखें और फालतू खर्च हटाएं। बिना साफ शर्तों के किसी को पैसा उधार न दें। करियर की दिशा को लेकर गंभीरता बढ़ेगी। मीन राशि में शनिदेव की उल्टी चाल पुराने पेंडिंग काम सामने ला सकती है। परेशान होने के बजाय पुरानी गलतियां सुधारें। आपकी बारीक नजर बहुत काम आएगी, दूसरों में कमियां न निकालें।

तुला राशिः संतुलित खर्च और बेहतर तालमेल पैसों के नियोजन पर ध्यान देना होगा। छोटे-छोटे खर्च धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं। कन्या राशि के शुक्रदेव खर्च की आदतों को सीधा रखने की सलाह देते हैं। दोस्तों को खुश करने के लिए फालतू खर्च न करें। दफ्तर में समझदारी से मामले संभालने होंगे। मिथुन राशि के मंगलदेव से भागदौड़ और बातचीत बढ़ेगी। एकादश भाव में बुधदेव और सूर्यदेव लोगों से जुड़ने में मदद करेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करियर के लिए नई राह खोल सकती है।

वृश्चिक राशिः भविष्य की योजना और धीरज से काम सोच-समझकर बनाई योजना से धन की स्थिति सुधरेगी। नवम भाव में गुरु बृहस्पतिदेव लंबे समय की सोच में मदद करेंगे। परिवार या घर के कामों पर खर्च हो सकता है। तुरंत फायदे के चक्कर में न पड़ें। आपकी लगन कठिन स्थिति को भी आसान बना देगी। मीन राशि में शनिदेव की उल्टी चाल पुराने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका देगी। अगर कोई पुरानी राह अब सही न लगे तो नया रास्ता चुनें। शांत रहकर की गई तैयारी रंग लाएगी।

धनु राशिः बचत में संतुलन और काम में साझेदारी कमाई के नए रास्ते खोजने का मन करेगा। पढ़ाई, यात्रा या निवेश पर खर्च हो सकता है। पूरी जानकारी जुटाकर ही फैसला लें। बजट का सही पालन करने से बिना वजह का दबाव नहीं बनेगा। दफ्तर में बातचीत से फायदा होगा। मिथुन राशि के मंगलदेव से साथियों के साथ मिलकर काम करना जरूरी रहेगा। कोई वादा करने से पहले देख लें कि आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। लोगों से जुड़ना तरक्की देगा।

मकर राशिः रुके काम निपटाना और काम में अनुशासन पैसों की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। काम या परिवार से जुड़े कुछ खर्च जरूरी हो सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं की सूची बनाएं। बिना सोचे-समझे नए लेन-देन से बचें, धीरज से बचत बढ़ेगी। काम में अनुशासन और निरंतरता रखनी होगी। मीन राशि में शनिदेव की उल्टी चाल पुरानी जिम्मेदारियों को सामने लाएगी। अगर पुराना काम दोबारा मिले तो उसे अच्छे से निपटाएं। आपकी लगन से वरिष्ठ अधिकारियों के बीच साख मजबूत होगी।

कुंभ राशिः सोच-समझकर निवेश और नई सोच आपकी राशि में राहु होने से जल्दी कमाई बढ़ाने का मन करेगा। जल्दबाजी और तुरंत फायदे वाली योजनाओं से दूर रहें। कन्या राशि के शुक्रदेव पैसों के कागजात और पेंडिंग बिलों की जांच करने की सलाह देते हैं। दफ्तर में कुछ नया करने का मन बनाएँगे। सूर्यदेव और बुधदेव आपकी सोच को निखारेंगे। अपनी योजनाएं पूरी तरह तैयार होने से पहले हर किसी के सामने न खोलें। काम की रणनीति गुप्त रखकर आगे बढ़ना सही रहेगा।

मीन राशिः शांत मन से फैसले और पेंडिंग काम का निपटारा आपकी राशि में चंद्रदेव और उल्टी चाल चल रहे शनिदेव होने से पुराने फैसलों पर ध्यान जाएगा। पुरानी गलतियों से सीख लें। शांत मन से अपनी बचत और खर्चों की योजना बनाएं और एक समय में एक कदम उठाएं। दफ्तर के माहौल का असर मन पर पड़ सकता है। बातों को दिल से न लगाएं। आपकी राशि में शनिदेव की उल्टी चाल पेंडिंग काम पूरा करने का मौका दे रही है। शांत रहकर लगातार काम करते रहें, नतीजे बेहतर मिलेंगे।

जन्माष्टमी से पहले घर में जरूर लेकर आएं ये चीजें, घर में रहेगी सुख समृद्धि

जन्माष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इन दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार हैं। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण के बाल रुप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। कहते है जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है वहां सुख समृद्धि हमेशा रहती है। साथ ही ऐसे घरों में भगवान विष्णु की कृपा भी सदैव बनी रहती है। ऐस्ट्रोलॉजर पिनाकी मिश्रा कहते हैं कि जन्माष्टमी से पहले घर में कुछ चीजें लाकर रख ली जाएं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी से पहले घर में कौनसी चीजें लाकर रखनी चाहिए। 1) जन्माष्टमी से पहले भगवान कृष्ण की बांसुरी लाकर जरूर रखें। एक लकड़ी की बांसुरी लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। ऐस्ट्रोलॉजर पिनाकी मिश्रा के अनुसार, बांसुरी को प्रेम, मधुरता, सकारात्मकता और जीवन में सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा स्थान या स्वच्छ और सम्मानित स्थान पर रखना चाहिए। 2) जन्माष्टमी से पहले एक गाय की बछड़े के साथ वाली प्रतिमा जरूर लेकर आना चाहिए। दरअसल, भगवान श्रीकृष्ण का गोसेवा और गौ-संस्कृति से

गहरा संबंध है। जन्माष्टमी के अवसर पर गाय-बछड़े की प्रतिमा या चित्र घर में रखना पारिवारिक सुख, पोषण और समृद्धि की भावना से जोड़ा जाता है। इस प्रतिमा को मंदिर में भगवान कृष्ण के पास रखें। या किसी स्वच्छ स्थान पर रखें और केवल सजावट की वस्तु न मानें। 3) जन्माष्टमी से पहले या उस दिन लक्ष्मी-नारायण की उपासना जरूर करें। ऐसा करने से घर पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। इस दिन आप श्री यंत्र भी लाकर घर में रख सकते हैं। मान्यता है इससे घर में धन संपत्ति बनी रहती है। 4) अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो जन्माष्टमी से पहले तुलसी का पौधा लाकर उसकी नियमित सेवा करें। ऐसा करने से घर में सुख संपत्ति और जीवन में मंगल कामना मिलती है। तुलसी को स्वच्छ स्थान पर रखें और नियमित रूप से जल अर्पित करें। 5) एस्ट्रोलॉजर पिनाकी मिश्रा के अनुसार, जन्माष्टमी की पूजा में घी का दीपक जलाना सात्विक और शुभ माना जाता है। पूजा के लिए शुद्ध गौघृत घर में लाना पवित्रता, प्रकाश और मंगल की भावना से जोड़ा जा सकता है।जन्माष्टमी की रात भगवान कृष्ण के जन्म समय के आसपास घी का दीपक जलाकर आराधना की जा सकती है।

खदानें बंद,अब आशियानों पर हथौड़ा डब्ल्यूसीएल पाथाखेड़ा के फरमान से मचा हड़कंप

पीके-1,पीके-2 और सारनी माइंस क्षेत्र के कर्मचारी आवास व औद्योगिक भवन होंगे डिस्मेंटल श्रमिक संगठनों की सहमति पर उठे सवाल, वर्षों से रह रहे परिवारों में बढ़ी बेचैनी

प्रमोद गुप्ता । पाथाखेड़ा

वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) पाथाखेड़ा क्षेत्र में बंद हो चुकी खदानों के बाद अब वर्षों पुराने कर्मचारी आवासों (एलसीएच,एमक्यू,टाइप टू) और औद्योगिक भवनों को खाली कराने की कवायद ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।आरोप है कि प्रबंधन द्वारा पीके-1, पीके-2 तथा सारनी माइंस क्षेत्र में निर्मित कर्मचारी आवास और अन्य भवनों को खाली कराने के बाद डिस्मेंटल करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में रहने वाले परिवारों में आक्रोश और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।सूत्रों के अनुसार, डब्ल्यूसीएल के संपदा अधिकारी उप क्षेत्र प्रबंधक सह कार्यालय की ओर से अलग-अलग क्षेत्रों में आवास खाली करने के नोटिस वितरित किए जा रहे हैं।अंबेडकर नगर, सुभाष नगर और मस्जिद चौक के आसपास स्थित आवासों को भी इस प्रक्रिया के दायरे में बताया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्षों से जिन आवासों में वे रह रहे हैं,उन्हें अचानक खाली करने के बाद उनका अगला ठिकाना क्या होगा।श्रमिक संगठनों की सहमति बनी सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल श्रमिक संगठनों की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि डब्ल्यूसीएल प्रबंधन और स्थानीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। इसमें बीएमएस, एचएमएस,सीटू और एटक सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में डब्ल्यूसीएल द्वारा निर्मित ऐसे आवासों और औद्योगिक भवनों को डिस्मेंटल करने की अनुमति पर सहमति बनी,जिनका उपयोग अब खदानें बंद होने के बाद नहीं हो रहा है।

यही निर्णय अब श्रमिकों और प्रभावित परिवारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का सवाल है कि जिन संगठनों ने वर्षों तक श्रमिक हितों और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी,क्या उन्हें इन आवासों में रहने वाले परिवारों के पुनर्वास और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। 334 से अधिक परिवार पहले से कानूनी पेंच मे पीके-1 और पीके-2 खदानों के बंद होने के बाद क्षेत्र में वन भूमि पर मकान बनाकर रहने वाले 334 से अधिक लोगों के खिलाफ वन विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने की बात भी सामने आ चुकी है। इनमें से कई मामले न्यायालय में विचाराधीन बताए जा रहे हैं। ऐसे में यदि एक ओर वन भूमि से जुड़े मामलों का कानूनी संकट बना हुआ है और दूसरी ओर डब्ल्यूसीएल अपने पुराने आवासों को खाली कराने तथा डिस्मेंटल करने की तैयारी कर रही है,तो प्रभावित परिवारों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।स्थानीय लोगों का तर्क है कि जब इन क्षेत्रों में कोयला खनन के लिए डब्ल्यूसीएल ने भूमि का अधिग्रहण किया था और अब खनन गतिविधियां बंद हो चुकी हैं,तो कंपनी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि का भविष्य क्या होगा। यदि भूमि का उपयोग खनन के लिए नहीं होना है तो नियमानुसार भूमि वापसी, पुनर्वास और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर भी स्पष्ट नीति सामने आनी चाहिए। चुनाव आते ही क्यों याद आती है खाली कराओ की कार्रवाई स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि नगरीय निकाय या विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही डब्ल्यूसीएल से जुड़े ऐसे आदेश और कार्रवाई चर्चा में क्यों आ जाती है। लोगों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान संवाद और पुनर्वास के माध्यम से होना चाहिए,न कि अचानक नोटिस देकर आशियाने खाली कराने से। दो पीढ़ियों से झुग्गियों और अस्थायी आवासों में जीवन गुजार रहे परिवारों के सामने अब एक और संकट खड़ा हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि उनके पास रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो केवल नोटिस के आधार पर उन्हें हटाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं होगा। फिलहाल मामला धीरे-धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। यदि डब्ल्यूसीएल प्रबंधन ने प्रभावित परिवारों की आपत्तियों और पुनर्वास की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया,तो क्षेत्र में विरोध की चिंगारी बड़े आंदोलन में बदल सकती है।स्थानीय लोगों ने संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो धरना,प्रदर्शन और व्यापक आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

सतपुड़ा ताप विद्युत गृह से 11 अधिकारी-कर्मचारी होंगे सेवानिवृत्त, अनुभव के एक और अध्याय का होगा समापन

31 अगस्त को सेवाकाल पूरा करेंगे कर्मचारी-अधिकारी, 1 सितंबर को विदाई समारोह में सम्मान के साथ होगी भावभीनी विदाई

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारनी में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले 11 अधिकारी-कर्मचारी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। इनके सेवानिवृत्त होने के साथ ही विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लंबे समय तक योगदान देने वाले अनुभवी कर्मचारियों के सेवाकाल का एक महत्वपूर्ण अध्याय पूरा हो जाएगा।सेवानिवृत्त होने वालों में प्रकाश घोरसे वरिष्ठ शीघ्र लेखक, गुणवंतराव पाटणकर, कार्यालय सहायक श्रेणी-1, इमारत सिंह बाईकर कार्यालय सहायक श्रेणी-2, पंढरीनाथ धोटे कार्यालय सहायक श्रेणी-2,शेषराव कावडकर संयंत्र पर्यवेक्षक, रामनाथ पांडोले संयंत्र पर्यवेक्षक,दिनेश कुमार पांडे वरिष्ठ संयंत्र सहायक, विजय कुमार संयंत्र सहायक,राजेंद्र कुमार संयंत्र सहायक,मुन्नालाल बारंगे सिविल परिचारक, मुरारी सिंदूर सिविल परिचारक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।इन कर्मचारियों ने अपने सेवाकाल के दौरान संयंत्र के विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां संभालते हुए विद्युत उत्पादन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। लंबे समय तक एक ही संस्थान से जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत्ति उनके लिए जहां नई शुरुआत होगी, वहीं सहकर्मियों के लिए अनुभव और कार्यशैली से जुड़े एक दौर की विदाई भी होगी।सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में 1 सितंबर को शाम 4 बजे मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की कैंटीन के ऊपर स्थित प्रशिक्षण हॉल में विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवाकाल और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के मुख्य अभियंता एसके लिल्होरे ने सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को समारोह में आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में सहकर्मी और अधिकारी उनके लंबे सेवाकाल को याद करते हुए भावभीनी विदाई देंगे।

राष्ट्रीय खेल दिवसः सारनी ए और जूनियर टीम ने जीते फुटबॉल मैच

रामरख्यानी में हुआ खेल स्पर्धा का समापन, नगर पालिका अध्यक्ष व जनप्रतिनिधियों द्वारा बांटे गए पुरस्कार

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नगर पालिका परिषद सारनी द्वारा तीन दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत रविवार को रामरख्यानी स्टेडियम में फुटबाल के दो मैचों का आयोजन किया गया।खेलेगा इंडिया,जीतेगा इंडिया थीम पर आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बरदे,सभापति भीम बहादुर थापा,पार्षद प्रवीण सोनी, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितेश शाक्य,के के भावसार, गुरुस्वामी एरुलू ,रंजीत डोंगरे एव मनीष धोटे की उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ।इस अवसर पर फुटबाल के दो मैच हुए। जिसमें सारनी ए और पाथाखेड़ा के बीच मैच खेला गया जिसमें सारनी ए ने 2-1 से मैच जीता। दूसरा मैच मप्रपाजन लिमिटेड के खिलाड़ी एवं नगर पालिका खिलाड़ी की मिलकर टीम और सारनी जुनियर क्लब के बीच खेला गया जिसमें सारनी जुनियर क्लब ने 3-0 से मैच जीता।फुटबाल प्रतियोगिता में लगभग 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया। सभी को शील्ड प्रमाण पत्र से पुरुस्कार देकर सम्मानित किया गया । बैडमिंटन प्रतियोगिता में लगभग नगर के 35 खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें सिंगल डबल के मैच हुए।विजेता उपविजेताओं सभी को शील्ड प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी कीर्ति नायक,राकेश डोंगरे निराकार सागर,राम प्रसाद दास मुकेश नागले प्रताप सिंदूर कामदेव सोनी उपस्थित थे।

बस किराया बढ़ा, ग्रामीणों की जेब पर पड़ा सीधा वार..!

बिना संवाद 40 प्रतिशत किराया वृद्धि से बढ़ी परेशानी,सारनी-भोपाल का सफर 250 से पहुंचा करीब 350 कांग्रेस ने सरकार से 20-35 प्रतिशत तक संशोधन की मांग की

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

प्रदेश में महंगाई और आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों के सामने निजी बसों के बढ़े किराए ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। निजी बस संचालकों द्वारा परिवहन किराए में अचानक करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का विरोध शुरू हो गया है।मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि तिरुपति एरोलू ने इस मामले में प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और बैतूल सड़क परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर किराया वृद्धि की समीक्षा करते हुए इसे 10 से 15 प्रतिशत तक सीमित करने की मांग की है।श्री एरोलू का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में लोग निजी बसों पर ही आवागमन के लिए निर्भर हैं। खासकर विद्यार्थी,मजदूर,छोटे व्यापारी,नौकरीपेशा लोग और सामान्य परिवारों के सदस्य रोजमर्रा के काम के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में किराए में एकमुश्त 40 प्रतिशत की वृद्धि सीधे उनकी जेब पर असर डाल रही है।उन्होंने सवाल उठाया कि जब डीजल के दाम में ऐसी कोई अचानक 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो यात्रियों से किराए में इतनी बड़ी वृद्धि किस आधार पर वसूली जा रही है। उनका आरोप है कि मध्यप्रदेश सड़क परिवहन व्यवस्था के बंद होने के बाद निजी बस संचालकों पर यात्रियों की निर्भरता बढ़ गई है। इसी का फायदा उठाकर कई मार्गों पर मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।श्री एरोलू के अनुसार,सारनी से भोपाल तक पहले करीब 250 रुपए किराया लिया जाता था,लेकिन 40 प्रतिशत वृद्धि के बाद यह राशि लगभग 350 रुपए तक पहुंच गई है। यानी एक यात्री को एक तरफ के सफर में ही करीब 100 रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। आने-जाने वाले व्यक्ति पर इसका बोझ करीब 200 रुपए तक पहुंच सकता है।सबसे ज्यादा असर उन ग्रामीण परिवारों पर पड़ रहा है जिनकी आय सीमित है। विद्यार्थियों और उनके साथ यात्रा करने वाले अभिभावकों के लिए लंबी दूरी का सफर अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सारनी से इंदौर सहित अन्य प्रमुख शहरों के मार्गों पर भी किराया बढ़ने से यात्रियों की चिंता बढ़ी है।सरकार से संवाद और नियंत्रण की मांग

कांग्रेस प्रतिनिधि ने परिवहन विभाग से मांग की है कि निजी बस संचालकों की किराया वृद्धि की जांच कर यात्रियों के हित में उचित किराया निर्धारित किया जाए। उनका कहना है कि सरकार को किराया तय करने से पहले यात्रियों,बस संचालकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करना चाहिए,ताकि ऐसा फैसला न हो जिसका सीधा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़े।श्री एरोलू ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और परिवहन विभाग ने इस मामले में जल्द हस्तक्षेप नहीं किया और किराया वृद्धि को संशोधित कर 10 से 15 प्रतिशत तक सीमित नहीं किया, तो कांग्रेस ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी की यात्रा सुविधा को महंगाई का नया जरिया नहीं बनने दिया जाएगा और इसके लिए सड़क से लेकर शासन स्तर तक आवाज उठाई जाएगी।

दस दिन से खुला पड़ा गड्ढा, हादसे का इंतजार..!

वार्ड 13 में जल आवर्धन योजना की लापरवाही से बढ़ा खतरा,रात में रोशनी नहीं होने से दोपहिया वाहन चालकों की बढ़ी चिंता

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

जल आवर्धन योजना के तहत पाइपलाइन में लीकेज सुधारने के लिए खोदा गया गड्ढा अब स्थानीय लोगों के लिए परेशानी के साथ-साथ हादसे का खतरा बनता जा रहा है। वार्ड क्रमांक 13 में मुख्य मार्ग के पास पाइप जॉइंट की मरम्मत को करीब दस दिन से अधिक समय बीत चुका है,लेकिन इसके बाद भी गड्ढे को अब तक बंद नहीं किया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार पाइपलाइन की मरम्मत और जॉइंट का काम पूरा होने के बाद गड्ढे को तत्काल भर दिया जाना चाहिए था। लेकिन काम पूरा होने के बाद भी सड़क के किनारे खुला गड्ढा छोड़ दिया गया। दिन में तो किसी तरह वाहन चालक इसे देखकर निकल जाते हैं, लेकिन रात के समय स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाती है। क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण गड्ढा दूर से दिखाई नहीं देता।पाथाखेड़ा के इस हिस्से में बड़ी संख्या में लोग पैदल,साइकिल और दोपहिया वाहनों से आवागमन करते हैं। ऐसे में अचानक सामने आने वाला गड्ढा विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी बड़े हादसे के बाद प्रशासन जागे,इससे पहले गड्ढे को बंद किया जाना चाहिए।सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि इस गड्ढे में गिरकर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है अथवा जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। जल आवर्धन योजना का काम करने वाली लक्ष्मी इंजीनियर कंपनी की या नगर पालिका परिषद सारनी के संबंधित अधिकारियों की सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का आरोप है कि मरम्मत कार्य के बाद स्थल को सुरक्षित करने में अनावश्यक देरी की जा रही है।उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी मौके का निरीक्षण करें और गड्ढे को तत्काल बंद कराकर चेतावनी संकेत व पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराएं, ताकि किसी अनहोनी से पहले समस्या का समाधान हो सके।

कचरे के ढेर पर सवाल, आबादी के बीच ट्रेंचिंग ग्राउंड..!

सारनी में नगर पालिका के स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से बढ़ा खतरा, आग,गंदा पानी और जहरीले धुएं से पांच वार्डों के रहवासी परेशान कांग्रेस अब न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में

दैनिक कारखाने का सफर। सारनी

जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद सारनी का ट्रेंचिंग ग्राउंड अब सिर्फ कचरा निस्तारण का स्थान नहीं रह गया है, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बनता जा रहा है।आबादी से बेहद कम दूरी पर संचालित हो रहे इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर पालिका के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बटेश्वर भारती के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड की अव्यवस्थाओं को लेकर 24 मार्च 2026 को नगर पालिका परिषद सारनी और 15 जुलाई 2026 को एसडीएम शाहपुर को लिखित शिकायत दी जा चुकी है।शिकायत में ट्रेंचिंग ग्राउंड में फैली अव्यवस्था, कचरे में लगने वाली आग और उससे आसपास के रहवासी क्षेत्रों में फैलने वाले धुएं से लोगों को होने वाली परेशानी का उल्लेख किया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि आग की घटनाओं में नगर पालिका की कार्रवाई स्थायी समाधान के बजाय महज खानापूर्ति तक सीमित रही। 20 मीटर दूर आबादी, नियमों पर उठे सवाल सबसे गंभीर सवाल ट्रेंचिंग ग्राउंड की लोकेशन को लेकर उठ रहा है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड कीप बाउंड्री वॉल से केवल 5 मीटर की दूरी पर आबादी है। इसका सीधा प्रभाव सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 22 पर पड़ता है। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 14 पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित करीब पांच वार्डों के रहवासी इसके प्रभाव क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। जबकि नियम के अनुसार टेंशन ग्राउंड से 20 मीटर के अलावा सुरक्षित महकमें के अनुरूप आबादी का शहर होना चाहिए।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कचरा निस्तारण केंद्रों को आबादी और संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए। ऐसे में इतने कम फासले पर ट्रेंचिंग ग्राउंड का संचालन कई सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी है कि स्थान चयन के समय स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मानकों का परीक्षण किस स्तर पर किया गया था। कचरे का पानी नालों से होकर जलाशय तक पहुंचने का आरोप मामला सिर्फ धुएं और दुर्गंध तक सीमित नहीं है। ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकलने वाले गंदे पानी और बारिश के दौरान कचरे से बहकर आने वाले दूषित पानी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक ट्रेंचिंग ग्राउंड क्षेत्र से निकलने वाले छोटे-छोटे नालों के माध्यम से यह पानी आगे सतपुड़ा जलाशय तक पहुंचता है।आरोप है कि दूषित पानी को रोकने,उसका वैज्ञानिक उपचार करने या उसके प्रवाह को जलस्रोतों तक पहुंचने से रोकने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। यदि यह स्थिति सही है तो इसका असर केवल आसपास की बस्तियों तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि पर्यावरण और जलस्रोतों की सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है। सूखा-गीला कचरा अलग करने की व्यवस्था पर भी सवाल वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में सूखे,गीले और खतरनाक कचरे का अलग-अलग संग्रहण और निस्तारण जरूरी माना जाता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सारनी के ट्रेंचिंग ग्राउंड में नगर पालिका के कंटेनरों और ठेकेदार के माध्यम से ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में पहुंचने वाला अलग-अलग प्रकार का कचरा एक ही स्थान पर डाला जा रहा है।इससे कचरे के ढेर में आग लगने, जहरीला धुआं उठने,दुर्गंध फैलने और आसपास के वातावरण के दूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी केवल कचरा उठाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण की निगरानी भी उसकी अहम जिम्मेदारी है। ऐसे में व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। संजय निकुंज की जमीन पर ट्रेंचिंग ग्राउंड कांग्रेस नेताओं ने भूमि आवंटन और स्थान चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस जमीन पर ट्रेंचिंग ग्राउंड संचालित किया जा रहा है,वह करीब साढ़े 14 एकड़ भूमि संजय निकुंज नर्सरी के नाम पर दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में यह जांच का विषय है कि भूमि का वास्तविक आवंटन किस उद्देश्य से हुआ था और बाद में इसका उपयोग ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए किस प्रक्रिया के तहत किया गया।कांग्रेस ने पर्यावरणीय अनुमति,भूमि डायवर्सन, स्थान चयन और कचरा निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग उठाई है। अब मामला न्यायालय तक ले जाने की तैयारी के बीच नगर पालिका परिषद सारनी के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग की कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मधुवर मोहन द्विवेदी द्वारा इंडिपेंडेट प्रेस, 11 प्रेस काम्पलेक्स, एमपी नगर जोन-1 भोपाल 462023 म.प्र. से मुद्रित एवं 201 ब्लाक ई, सागर प्रीमियम टावर जेके हॉस्पिटल, कोलार रोड, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित।
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल न्यायालय रहेगा) संपादक- सुनील यादव, समाचार संपादक- राहुल कौशिक। फोन नं. 0755-4262585-9425006706, मो. नंबर 9826697203, 9926288166, RNI.No. MPHIN/2020/78949